मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | भोपाल, रविवार 18 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-333, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंध्र प्रदेश में की प्रमुख निवेशकों से भेंट, जीआईएस 2027 के लिये किया आमंत्रित

मध्यप्रदेश में निवेश हर दृष्टि से आपको लाभ देगा : मुख्यमंत्री

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश में निवेशकों से मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास की प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर उन्हें हर स्थिति में लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को आंध्र प्रदेश में निवेशकों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेश के नए अवसरों और औद्योगिक साझेदारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी निवेशकों को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा में बताया कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं और अनुकूल औद्योगिक वातावरण का लाभ सभी को मिल रहा है। राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन की 25 सरलीकृत नीतियां



विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आने में सहायक बन रही हैं। मध्यप्रदेश में धार जिले में पीएम मित्र पार्क और ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकाई में महत्वपूर्ण निवेश अब क्रियान्वयन की ओर है। हाल ही में जबलपुर-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर की योजना तैयार की गई है। यह कॉरिडोर प्रदेश के बड़े व्यापक भू-भाग की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विजयवाड़ा में सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री विजय देवरकोंडा एवं अभिनेत्री श्रीमती रश्मिका मंदाना से भी भेंट हुई।

निवेशकों से की वन-टू-वन चर्चा

टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मोहन स्पिनटेक्स इंडिया लिमिटेड के संस्थापक एवं प्रबंध संचालक श्री वी. सुधाकर चौधरी तथा श्री अनंत लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स के अध्यक्ष श्री सामिनेनी कोटेश्वर राव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों उद्योगपतियों को धार स्थित पीएम मित्रा पार्क और प्रदेश के कपास उत्पादक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। चर्चा में स्पिनिंग, होम टेक्सटाइल, बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रदेश में उपलब्ध अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। श्री चौधरी के साथ कृभको के अध्यक्ष के रूप में जैव-उर्वरक, कृषि आदान और कृषि लॉजिस्टिक्स में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में देश में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

प्रदेश की फिल्म-फ्रेंडली नीतियां, फिल्म निमार्ताओं को आकर्षित करने में सफल हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को जीआईएस : 2027 का आमंत्रण देते हुए आयोजन की रूपरेखा की जानकारी दी जिसमें भोपाल में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक एकत्र होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी जिसमें 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। इन प्रस्तावों में से एक तिहाई प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तेनाली डबल हॉर्स के प्रबंध संचालक श्री मोहन श्याम प्रसाद के साथ प्रदेश के दलहन उत्पादक क्षेत्रों के समीप दाल मिल स्थापित करने की संभावनाओं पर संवाद हुआ। कॉन्टिनेंटल कॉफी के महाप्रबंधक श्री मीनावल्ली बलराम से उत्तर और मध्य भारत के बाजारों में आपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश में कॉफी ब्लेंडिंग, पैकिंग एवं वितरण केंद्र विकसित करने पर विचार-विमर्श किया गया।

लालकृष्ण आडवाणी को सीने में इन्फेक्शन, अपोलो अस्पताल में भर्ती

एजेन्सी, **नई दिल्ली**



भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को शुक्रवार देर शाम सीने में इंफेक्शन के चलते दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है।

अस्पताल के मुताबिक,उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता जे.पी. नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे अस्पताल लाया गया। उन्हें फेफड़ों के विभाग में भर्ती किया गया है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। लालकृष्ण आडवाणी 98 साल के हैं और दिल्ली में लुटियंस जोन के 30, पृथ्वीराज रोड स्थित अपने सरकारी बंगले में रहते हैं। उनकी पत्नी कमला आडवाणी का निधन साल 2016 में हो गया था, जिसके बाद से उनकी देखरेख का पूरा जिम्मा उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी संभालती हैं।

पड़ोसी बोले- प्रॉपर्टी विवाद था, सास ने नूडल्स बनाए, इसमें जहर होने का शक

ग्रेटर नोएडा- घर में पति-पत्नी 3 बच्चों की लाश मिलीं

एजेन्सी, **नोएडा**

यूपी में ग्रेटर नोएडा के नंगला श्रीपदम गांव में शनिवार को एक घर में पति-पत्नी और उनके 3 बच्चों की लाश मिली। सुबह काफी देर तक परिवार नहीं उठा तो पड़ोसियों को शक हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो पांचों बिस्तर पर पड़े थे। एक के मुंह से झाग निकल रहा था।

पुलिस घर पहुंची तो पिता बेटे से लिपटे हुए चारपाई पर मृत मिले। दूसरे बिस्तर पर मां छोटे बेटे और बेटी से लिपटी हुई थीं। मृतकों की पहचान महेश (37), पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू (11), साक्षत (3) और बेटी मिष्टी (7) के रूप में हुई है। डीसीपी श्रवण



कुमार सिंह ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलेगी। वहीं, पड़ोसियों का आरोप है कि प्रॉपर्टी को लेकर महेश का अपनी मां से अक्सर झगड़ा होता था।

मां कहती थी कि सब कुछ बेटी और दामाद के नाम कर देंगी। पड़ोसियों ने मां पर नूडल्स में जहर मिलाकर देने का भी आरोप लगाया। घटनास्थल जेवर एयरपोर्ट से 6 किमी और जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर है। मां चंदो ने बताया- महेश और बाकी लोगों ने शुक्रवार रात करीब 10 बजे नूडल्स खाए। फिर सभी सोने चले गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नूडल्स नहीं खाए। महेश रोज सुबह जल्दी उठता था, शनिवार को काफी देर तक नहीं उठा तो शक हुआ।

महेश की भाभी नीरज ने बताया- मेरा आदमी खत्म हुआ, तो मुझे घर से भगा दिया। मेरी 14 साल की लड़की है। उसे भी साथ नहीं रखा। मैं उसे लेकर किराए के घर में रहती हूं। महेश ने कहा था कि भाभी, तू टाइम काट ले, कुछ दिनों की बात है।

सरकार से समझौता करने का दबाव

नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान छोड़ सकते हैं इमरान खान



एजेन्सी, **नई दिल्ली**

पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व ढट इमरान खान भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह देश छोड़ सकते हैं। विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया। अचकचई ने कहा सरकार इमरान पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। वे नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की तरह देश छोड़कर जा सकते हैं।

73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर सिफर, अल-कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह समेत करीब 200 मामले दर्ज हैं।

महमूद खान अचकजई की राजनीति में एंट्री 1973 में पिता की हत्या के बाद हुई। उनके पिता पश्तूनों के अधिकारों और अलग राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष करते थे।

अभी वे पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अध्यक्ष हैं और संसद में विपक्षी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। नब्बे के दशक में वे नवाज शरीफ की पार्टी के सहयोगी थे। 2014 में जब इमरान खान ने नवाज सरकार के खिलाफ धरना दिया, तब अचकजई ने नवाज का समर्थन किया था। बाद में संविधान की रक्षा और विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर उनकी पार्टी इमरान के करीब आई।

तेज बारिश के बीच बिगड़े हालात

कोलकाता के दुर्गा पंडाल में भगदड़, 18 मौत 45 घायल, बारिश से बचने के लिए जमा थी भीड़



एजेन्सी, **कोलकाता**

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शनिवार शाम चोरबागान दुर्गा पंडाल में भगदड़ मच गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 पुरुष, 13 महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। हालांकि, कोलकाता मेडिकल कॉलेज के सूत्रों ने 20 लोगों की मौत का दावा किया है। हादसे में 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

कोलकाता पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम बारिश शुरू हुई। इससे बचने के लिए कई लोग पंडाल के अंदर रुक गए। इसी दौरान करीब 7:40 बजे नए दर्शकों के प्रवेश की कोशिश के बीच धक्का-मुक्की होने लगी और भगदड़ मच गई।

हादसे के बाद पंडाल की लाइटें बंद कर दी गईं और लोगों की एंट्री रोक दी गई। घटना के बाद कई अन्य दुर्गा पूजा पंडाल भी बंद कर दिए गए हैं। बंगाल सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003455678 जारी किया है।

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पंडाल में प्रवेश और बाहर निकलने के रास्तों को लेकर सही तरीके से घोषणाएं नहीं की गईं। भीड़ को संभालने के लिए भी जरूरी निर्देश नहीं दिए गए। इससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई और अफरा-तफरी मच गई। वहीं, कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंडाल में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे। पुलिस की तैनाती सिर्फ वीआईपी गेट पर थी।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

भोपाल से खाटूश्यामजी जा रहे थे

मिनी बस एक्सप्रेसवे से नाले में गिरी, 8 की मौत



एजेन्सी, **कोटा**

राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैंपो ट्रैवलर (मिनी बस) पुलिया से गिर गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले थे। एक्सीडेंट शनिवार सुबह 6 बजे सिमलिया थाना क्षेत्र में हुआ। SHO नंद सिंह ने बताया कि ट्रैवलर भोपाल से खाटूश्यामजी जा रहा था। कोटा शहर से 35 किलोमीटर दूर कराड़िया टोल के पास ट्रैवलर पुलिया से 15 फीट नीचे गिर गया। एक्सीडेंट में 17 पैसेंजर्स घायल हुए हैं। अंधेरे के कारण रेस्क्यू में कुछ देरी भी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि कई डेडबॉडी सीटों के बीच फंसी थीं। उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर खींचा गया। घायलों को खिड़की तोड़कर निकाला गया। रेस्क्यू करने पहुंची टीम के एक मेंबर ने बताया कि आशंका है कि बस एक्सप्रे-वे से नीचे बोनट की तरफ से टकराई हो। क्योंकि अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि एक बॉडी डैश बोर्ड के कांच को तोड़ते हुए बाहर आ गई थी।

पाकिस्तान में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप

बलूचिस्तान में बस रोककर 20 पुलिस अफसरों को किया किडनैप!

एजेन्सी, **नई दिल्ली**

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद लोगों ने 20 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया। घटना शनिवार को घटी। पुलिस के मुताबिक, सभी प्रशिक्षु कलात जिले के एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे थे। वे सप्ताहांत की छुट्टी में घर जा रहे थे। तभी मस्तुंग के पास क्वेटा-कराची हाईवे पर हथियारबंद लोगों ने उनकी बस रोक ली।

चालक और तीन नागरिकों को छोड़ा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे। उन्होंने बस के चालक को वाहन अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया। बाद में चालक और बस में सवार तीन अन्य नागरिकों को छोड़ दिया गया। लेकिन 20 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को हमलावर अपने साथ ले गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। अब तक किसी संगठन या व्यक्ति ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।



अलगाववादी संगठनों और टीटीपी के खिलाफ अभियान जारी

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों और प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को निशाना बनाया जा रहा है। ये अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए जा रहे हैं।

जुलाई में 27 पुलिसकर्मियों की हुई थी मौत

बलूचिस्तान में इससे पहले भी बड़े हमले हो चुके हैं। जुलाई में आतंकियों ने प्रांत में कम से कम तीन जगहों पर हमले किए थे। इनमें जियारत के मांगी बांध स्थित पुलिस चौकी पर हुआ हमला भी शामिल था। आतंकियों ने पहले नौ पुलिसकर्मियों की हत्या की। इसके बाद 18 अन्य पुलिसकर्मियों को अगवा कर लिया। इस हमले में कुल 27 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। बाद में सभी 18 अगवा पुलिसकर्मियों के शव जियारत के पास जरघून के पहाड़ी इलाके में मिले थे।

पिछले महीने 23 लोगों को बचाया गया

पिछले महीने कलात में हाईवे पर स्थित एक चौकी से 23 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। इस दौरान पांच आतंकियों को मार गिराया गया। साथ ही, अपहृत सभी 23 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था।

बलूचिस्तान में बढ़ रही अपहरण की घटनाएं

अफगानिस्तान की सीमा से सटे बलूचिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। यहां नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। अपहरण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इन घटनाओं को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज कर दिए हैं। फिलहाल 20 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है।

अपहरण के पीछे किसका हाथ, अभी पता नहीं

पुलिस ने बताया कि अब तक किसी संगठन या व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, यह वारदात ऐसे समय हुई है, जब पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों और प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चला रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अगवा किए गए पुलिसकर्मियों का पता लगाने में जुटी हैं।

स्कूल में पढ़ाई की हकीकत जानने छात्र बने कमिश्नर, अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

जबलपुर कमिश्नर धनंजय सिंह छात्र बन कर स्कूल पहुंचे, शिक्षा की खोली पोल

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को संभागायुक्त धनंजय सिंह अचानक मझौली तहसील के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। पौंडा गांव के शासकीय स्कूल में वे छात्र बनकर बेंच पर बैठे और शिक्षक से पढ़ाई की स्थिति जानी। निरीक्षण में अध्यापन कार्य अपेक्षित स्तर का नहीं मिलने पर उन्होंने शिक्षकों की क्लास ली। साथ ही संबंधित बीईओ और बीआरसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने स्कूली बच्चों से संवाद कर रोजाना होने वाली पढ़ाई की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों के करियर काउंसलिंग के संबंध में भी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान पढ़ाई का स्तर अपेक्षित नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। सहकारी संस्था में खाद वितरण का सत्यापन करने को कहा संभागायुक्त ने पौंडा स्थित सहकारी संस्था में खाद वितरण की जानकारी ली। उन्होंने संयुक्त आयुक्त सहकारिता को खाद वितरण का सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा संभागायुक्त ने पौड़ा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण कर चिकित्सकीय स्टाफ और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, एएनसी पंजीयन और मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति की जानकारी ली। भर्ती मरीजों से उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी पूछा। उन्होंने ओपीडी पंजी का निरीक्षण कर टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना के प्रकरणों की जानकारी ली। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को गुणवत्तापूर्ण उपचार, आवश्यक दवाओं की सतत उपलब्धता और एएनसी पंजीयन की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी का निरीक्षण करते हुए कमिश्नर। आंगनवाड़ी का निरीक्षण करते हुए कमिश्नर। आंगनवाड़ी की मॉनिटरिंग में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश संभागायुक्त ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों के पोषण, वजन, खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। केंद्र के संचालन की समुचित मॉनिटरिंग नहीं किए जाने पर संबंधित सीडीपीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने पौंडा स्थित गौशाला का निरीक्षण कर संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद जल जीवन मिशन के तहत गांव की एकल नलजल योजना के कार्यों की जानकारी ली। योजना का काम समयसीमा में पूरा नहीं करने और समुचित मॉनिटरिंग नहीं किए जाने पर सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान संभागायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद कर पेयजल, खाद और राशन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनहित से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।

रिकवरी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची फर्म

हाईकोर्ट ने खारिज की पैसिफिक एक्सपोर्ट की याचिका, कलेक्टर को दिया 4 महीने का समय

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



आयरन ओर के कथित अवैध खनन से जुड़े मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक से संबंधित एक और फर्म को हाईकोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संजय पाठक से जुड़ी पार्टनरशिप फर्म पैसिफिक एक्सपोर्ट की याचिका खारिज कर दी। फर्म ने जबलपुर कलेक्टर की ओर से जारी 81.73 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन से जुड़े मामले में कार्रवाई करने का अधिकार कलेक्टर को है। फर्म अपना पक्ष कलेक्टर के समक्ष रख सकती है। कोर्ट ने कलेक्टर को चार महीने के भीतर मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 8 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसी मामले से संबंधित आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन की याचिका भी खारिज कर दी थी। अधिवक्ता पंकज कुमार दुबे के मुताबिक शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक संजय पाठक से संबंधित फर्मों के खिलाफ चल रही करीब 443 करोड़ रुपए और उस पर देय जीएसटी की रिकवरी संबंधी कार्रवाई में राहत देने से इनकार कर दिया। मामला वर्ष 2004 से 2017 के बीच का है। आरोप है कि इस दौरान संजय पाठक से संबंधित फर्मों ने निर्धारित सीमा से अधिक खनन (एक्सेस माइनिंग) किया था। इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर के समक्ष कार्रवाई चल रही है। इस मामले से संबंधित पांच प्रकरणों में से एक आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन की याचिका 8 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी थी। इस बेंच में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा शामिल थे। अब इसी मामले में संबंधित दूसरी फर्म पैसिफिक एक्सपोर्ट को भी राहत नहीं मिली है। इसके डायरेक्टर सुमित अग्रवाल हैं और फर्म के खिलाफ करीब 81 करोड़ रुपए की रिकवरी का मामला है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2025 से फर्म को बार-बार समय दिया गया और नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन फर्म की ओर से अब तक जवाब नहीं दिया गया और न ही कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुई। अदालत ने फर्म को अपना पक्ष कलेक्टर के सामने रखने की छूट देते हुए मामले का चार महीने में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि मामला पिछले छह से आठ महीने से लंबित है। न्यायालय ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

रास्ते में पिट रहीं रीवा, रायपुर और अंबिकापुर इंटरसिटी ट्रेन

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



जबलपुर और इसके आसपास के इलाकों को आपस में जोड़ने वाली तीन प्रमुख इंटरसिटी ट्रेनों का लगातार लेट होना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। रीवा इंटरसिटी और रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने तय समय से काफी विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, अंबिकापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी रास्ते में लंबी अवधि के लिए रोके जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यात्रियों का कहना है कि इन महत्वपूर्ण ट्रेनों को अक्सर स्टेशनों के बाहरी हिस्सों यानी आउटर पर घंटों तक खड़ा रखा जाता है। रेलवे ट्रैक पर अन्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को निकालने की प्राथमिकता के चलते इन इंटरसिटी ट्रेनों की रफ्तार बीच रास्ते में ही थम जाती है। दैनिक यात्रियों और आगे की यात्रा करने समय पर अपने गंतव्य तक न पहुंच पाने के कारण इन ट्रेनों से रोजाना आवाजाही करने वाले नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और छात्रों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसके अलावा, जिन यात्रियों को इन ट्रेनों से उतरकर आगे की लंबी यात्रा के लिए अन्य कनेक्टिंग ट्रेनें या साधन पकड़ने होते हैं, वे भी ट्रेनें लेट होने के कारण काफी परेशान हैं। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि इन ट्रेनों के संचालन समय में सुधार किया जाए और रास्ते में अनावश्यक देरी को रोका जाए।

भारी वाहनों की नो-एंट्री का समय बदला

जबलपुर में देवी पंडालों के दर्शन को उमड़ेंगे श्रृद्धालु रात दो बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



शारदीय नवरात्रि व दुर्गोत्सव पर्व के पावन अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में आस्था और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही शहर के विभिन्न भव्य पूजा पंडालों में देवी मां के दर्शन और पूजन-अर्चन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। शहर के मुख्य व्यावसायिक इलाकों से लेकर तंग गलियों तक में रात के समय आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है। सड़कों पर लगातार बढ़ रही इस अप्रत्याशित भीड़ और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जबलपुर पुलिस एवं यातायात विभाग ने शहर की संपूर्ण ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों की 'नो-एंट्री' के समय में बड़ा विस्तार किया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भारी वाहनों के शहर की सीमा में प्रवेश पर रोक के समय को बढ़ाकर अब देर रात 2:00 बजे तक कर दिया गया है। इस संशोधित आदेश के लागू होने के बाद, अब सभी प्रकार के भारी कमर्शियल वाहनों को सुबह 6:00 बजे से लेकर देर रात 2:00 बजे के मध्य शहर की आंतरिक सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इन वाहनों को शहर के बाहरी आउटर रिंग रोड और बाईपास मार्गों पर ही रोका जाएगा। यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि देर रात 2:00 बजे की समय-सीमा तय किए जाने के बावजूद, यदि शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है या सुरक्षा के लिहाज से आवश्यकता महसूस होती है, तो रात 2:00 बजे के बाद भी भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने से पूरी तरह रोका जा सकता है।

मध्य प्रदेश की अदालतों में 21.42 लाख केस पेंडिंग, इनमें 36 हजार को 10 साल से फैसले का इंतजार



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

न्याय की आस में अदालतों की चौखट पर पहुंचने वाले लाखों वादकारियों के लिए मुकदमों का फैसला अब एक लंबी और थका देने वाली प्रतीक्षा बन चुका है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के साथ-साथ राज्य की पूरी अधीनस्थ न्यायपालिका पर मुकदमों का भारी दबाव बना हुआ है। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 30 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में कुल 21,42,280 मामले लंबित पड़े हैं। इनमें से 3,48,670 मामले ऐसे हैं जो पांच साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं, जबकि 36,080 मामले तो ऐसे हैं जिन्हें दस साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन उनका निपटारा नहीं हो सका है। न्याय में हो रही इस लंबी देरी से अदालतों में बढ़ते मुकदमों के बोझ और न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जबलपुर जिले में छह महीने में पांच साल से कम उम्र के 643 बच्चों की मौत, 20 प्रतिशत रेफर होकर आए

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



जिले में पांच साल तक के बच्चों की मृत्यु के आंकड़े बेहद चिंताजनक स्थिति बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की फैक्ट फाइल के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच महज छह महीने के भीतर जिले में कुल 643 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें से 553 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र एक साल से भी कम थी, जबकि 445 नवजात बच्चे जन्म से लेकर मात्र 28 दिन के भीतर ही दुनिया छोड़ गए। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, 643 बच्चों में से 601 मौतें संस्थागत यानी अस्पतालों में इलाज के दौरान हुईं, जबकि 42 बच्चों ने घर पर या अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि इन कुल मौतों में से लगभग 20 प्रतिशत मामले अन्य पड़ोसी जिलों से रेफर होकर आए केसों के हैं। सिवनी, मंडला, डिंडोरी, कटनी और नरसिंहपुर जैसे आसपास के जिलों से गंभीर व नाजुक हालत में बच्चों को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और एल्गिन अस्पताल रेफर किया जाता है। इनमें से कई नवजात और शिशु ऐसी गंभीर अवस्था में पहुंचते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिसके चलते ये दुखद आंकड़े जबलपुर के खाते में दर्ज हो गए हैं।

दूध के दाम में उछाल, एक महीने में 70 से 80 रुपये प्रति लीटर हुई कीमत

जबलपुर में महंगाई का झटका, दूध की कीमत 80 रुपये लीटर पहुंची

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



जबलपुर शहर में पिछले एक महीने के भीतर दूध की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी होने से आम उपभोक्ताओं का घरेलू बजट बुरी तरह चरमरा गया है। शहर में जो दूध पहले 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था, उसकी कीमत अब बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। अचानक हुई इस मूल्यवृद्धि को लेकर स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों में रोष व्याप्त है। दूध के दामों में हुई इस अचानक बढ़ोतरी पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध जताते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समिति के मध्यभारत समन्वयक बलवंत सिंह गुर्जर ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा कि दूध हर परिवार की एक बेहद जरूरी और बुनियादी दैनिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के दैनिक पोषण और स्वास्थ्य में दूध की अहम भूमिका होती है, ऐसे में इसके दामों में अचानक उछाल आना बेहद चिंताजनक है। इस बेकाबू महंगाई के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों, गरीब तबके और विशेष रूप से पेंशन पर जीवनयापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ पड़ा है, जिससे पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे परिवारों की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।

ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, आरोप-प्रत्यारोप तेज

ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज, तन्खा ने सरकार तो राकेश सिंह ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



एमपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में आरक्षण के पक्ष में मजबूती से दलीलें नहीं रखीं और न ही जरूरी आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण के मामले में धोखा देने का आरोप लगाया है। शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे विवेक तन्खा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। हालांकि, इसे अदालत में डिफेंड करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की थी, क्योंकि बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा सत्ता में आ गई। तन्खा ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने स्पष्ट किया था कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% होती है। इससे अधिक आरक्षण देने के लिए सरकार को असाधारण परिस्थितियों के समर्थन में मात्रात्मक आंकड़े (क्वांटिफायबल डेटा) प्रस्तुत करने होते हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से लगता है कि सरकार पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर पाई। यदि जरूरी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते, तो संभव है कि फैसला अलग होता। अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। तन्खा के मुताबिक, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए असाधारण परिस्थितियां साबित करना और पर्याप्त आंकड़े पेश करना जरूरी होगा। तन्खा ने कहा कि राजनीतिक दल स्वयं इस तरह की याचिका दायर नहीं कर सकते। पार्टी के पदाधिकारी अपनी ओर से पक्ष रख सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं या कानूनी लड़ाई में समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अध्यादेश का बचाव करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। संबंधित तथ्य और आंकड़े भी सरकार के पास ही होते हैं। जबलपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है, तो यह सही कदम है। उन्होंने पहले भी सुझाव दिया था कि सरकार को स्वयं आगे आकर कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि कानून का बचाव तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सरकार ही बेहतर तरीके से कर सकती है। मंत्री राकेश सिंह बोले- कांग्रेस ने आरक्षण के मामले में धोखा किया इधर, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण के मामले में धोखा किया है। हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार जो विधेयक लेकर आई थी, वह जल्दबाजी में तैयार किया गया और उसमें कमियां थीं।राकेश सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो विधेयक लेकर आई थी, वह बेहद जल्दबाजी में तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि उस विधेयक में कई गंभीर विधिक कमियां और खामियां थीं, जिसके कारण आज यह स्थिति निर्मित हुई है। लोक निर्माण मंत्री ने राज्य सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का मुख्य प्रयास और प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों के साथ पूर्ण न्याय हो और नियम-कानून के तहत ही सभी कदम उठाए जाएं।

चंदेरी में अस्पताल के लिए निर्धारित स्थल का निरीक्षण करते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा अस्पताल: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

■ एक सत बुलेटिन, **चंदेरी/अशोकनगर**

स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयास से चंदेरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य आधुनिक अस्पताल के निर्माण कवायद शुरू हो गई है। चंदेरी प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शनिवार को अस्पताल स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से परियोजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अस्पताल निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के



निर्देश दिए। स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अस्पताल के लिए निर्धारित स्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश



अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसमें मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओपीडी कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, प्री-एवं पोस्ट-ऑपरेटिव वार्ड, आपातकालीन वार्ड, एक्स-रे कक्ष और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पांच बिस्तरों की नवजात शिशु देखभाल इकाई, लेबर रूम, टीकाकरण संबंधी सुविधाएं, प्रतीक्षालय तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है। प्रथम तल पर 40 बिस्तरों वाला मुख्य वार्ड, डॉक्टरों के ड्यूटी रूम और बैठक कक्ष बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा पर जोर निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया। अस्पताल के निर्माण से चंदेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे मरीजों को उपचार के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम करने की दिशा में भी लाभ मिलने की उम्मीद है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद चंदेरी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नया आधार मिलेगा और स्थानीय नागरिकों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

1100 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने दीं गरबा प्रस्तुतियां, पुलिस परिवारों ने जताया आभार

डीजीपी मकवाणा की मौजूदगी में मध्यप्रदेश पुलिस गरबा महोत्सव का भव्य समापन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

पुलिस परिवारों के मनोरंजन, सांस्कृतिक जुड़ाव और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस लाइन, नेहरू नगर में आयोजित दो दिवसीय मध्यप्रदेश पुलिस गरबा महोत्सव का शनिवार को उत्साहपूर्ण समापन हुआ। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मां अम्बे की आरती कर दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में पुलिस परिवारों की 1100 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने धार्मिक एवं फिल्मी धुनों पर आकर्षक गरबा प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में जिला पुलिस बल भोपाल के साथ सातवीं, 23वीं और 25वीं वाहिनी के पुलिस परिवारों की महिलाओं एवं बालिकाओं ने भाग लिया। पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके परिजनों ने भी आयोजन में



शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह के समापन पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए और सभी को बधाई दी। उन्होंने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए कल्याण शाखा तथा आयोजन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। आयोजन से प्रसन्न पुलिस परिवारों ने इस पहल के लिए डीजीपी के प्रति आभार व्यक्त किया। महोत्सव की तैयारियों के लिए पुलिस लाइन और संबंधित वाहिनियों में गरबा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे, जहां प्रतिभागियों ने सामूहिक प्रस्तुतियों का अभ्यास किया। गरबा महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2022 में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना की धर्मपत्नी प्रियंवदा सक्सेना की परिकल्पना से हुई थी। अब यह आयोजन वार्षिक परंपरा बन चुका है। पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था और जनसेवा की जिम्मेदारियों के चलते त्योहारों पर भी ड्यूटी करते हैं। ऐसे में यह महोत्सव उनके परिवारों को सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने और आपसी मेलजोल बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

साहित्य परिषद की ग़ज़ल गोष्ठी में शायरों ने बांधे संवेदनाओं के शब्द



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

अखिल भारतीय साहित्य परिषद की भोपाल इकाई के तत्वावधान में शनिवार को संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा में ग़ज़ल गोष्ठी आयोजित की गई। वरिष्ठ ग़ज़लकार दिनेश मालवीय की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में शहर के अनेक रचनाकारों ने अपनी ग़ज़लों के माध्यम से जीवन, समाज, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में परिषद की अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉ. नुसरत मेहदी ने स्वागत करते हुए ग़ज़ल विधा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ग़ज़ल कम शब्दों में गहरी बात कहने की सशक्त विधा है। इसकी संक्षिप्तता, प्रतीकात्मकता और भावनात्मक गहराई इसे विशिष्ट बनाती है। महेश श्रीवास्तव ने शेर सुनाया, 'ज़िंदगी अपनी खंगालो ध्यान से, रत्न सबके सब नहीं मिलते समंदर में।' दिनेश प्रभात ने 'तीखे-तीखे नयना भी आर-पार होते हैं, कौन कहता चाकू ही धारदार होते हैं' के माध्यम से दृष्टि की तीक्ष्णता को रेखांकित किया। किशन तिवारी ने जीवन में रौशनी और खुशबू की कमी को अपने शेर में व्यक्त किया। वहीं अशोक निर्मल ने बेटियों के प्रति सामाजिक संवेदना और अभाव के सवाल को अपनी रचना में उठाया।

भोपाल में 21 आवारा पशु कांजी हाउस भेजे बीमार और घायल पशुओं का होगा उपचार

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को हटाने के लिए नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। शनिवार को निगम के गोवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने विभिन्न क्षेत्रों से 21 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा, जबकि सात बीमार और घायल पशुओं को आसरा पशु चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं, निगम की हांका पार्टी ने 15 पशुओं को सड़कों से हटाया। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत करोंद चौराहा, भोपाल मेमोरियल अस्पताल, भानपुर, शिवनगर, छोला दशहरा मैदान, 80 फीट करोंद मंडी, खजूरी कलां रोड, पिपलानी, गांधी



चौक और जंबूरी मैदान सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इसके अलावा भीलवाड़ा साक्षी रावत क्षेत्र, चूना भट्ठी चौराहा, कोलार रोड स्थित मदर टेरेसा क्षेत्र, शाहपुरा, अटल भवन, 74 बंगले, लिंक रोड नंबर 1, 2 और 3 तथा बिट्टन मार्केट में भी पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं के विचरण से होने वाली परेशानी को कम करने और बीमार व घायल पशुओं को उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है।

खुले में कचरा फेंकने पर रहवासी से वसूला एक हजार जुर्माना

भोपाल। शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम के अमले ने परशुराम चौराहे के पास खुले में कचरा फेंकने वाले एक रहवासी से एक हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम अमले द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। शनिवार को जोन क्रमांक 16 के अमले ने वार्ड क्रमांक 68 में निरीक्षण के दौरान परशुराम चौराहे के पास एक रहवासी को खुले में कचरा फेंकते हुए पाया। इस पर जोनल अधिकारी रजनीश वशिष्ठ और वार्ड प्रभारी नरेश साहू ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित रहवासी से एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला।खुले में कचरा न फेंकें।

कैंसर के खिलाफ दौड़ेगा भोपाल, 25 अक्टूबर को एम्स में होगा 'रन फॉर लाइफ' आयोजन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच एवं उपचार का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एम्स भोपाल में 25 अक्टूबर 2026, रविवार को 'रन फॉर लाइफ-रन अगेंस्ट कैंसर' ग्रीन रन का आयोजन किया जाएगा। दौड़ सुबह 6 बजे एम्स परिसर स्थित कौटिल्य भवन से शुरू होगी। इसका आयोजन एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा अन्य शैक्षणिक विभागों के सहयोग से किया जा रहा है। हर उम्र और क्षमता के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दौड़ को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें धावकों और फिटनेस प्रेमियों के लिए 5 किलोमीटर की ग्रीन रन, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, उनके परिवारों और आम नागरिकों के लिए 3 किलोमीटर की फन रन या वॉक तथा बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और कैंसर से उबर चुके लोगों के लिए 1 किलोमीटर की ग्रीन वॉक रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, कैंसर की शीघ्र पहचान, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। दौड़ के



बाद एम्स परिसर में पौधारोपण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कैंसर को मात देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उनकी प्रेरक कहानियों के माध्यम से समय पर जांच और उपचार के महत्व को रेखांकित किया जाएगा। आयोजकों ने भोपाल और आसपास के नागरिकों से बड़ी संख्या में भाग लेकर कैंसर जागरूकता अभियान को सफल बनाने की अपील की है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में भोपाल और रायसेन जिले की कोर ग्रुप एवं जिला बैठक आयोजित

संगठन की मजबूती के लिए जनसंपर्क और सेवा कार्यों में सक्रियता जरूरी: चंद्रशेखर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भोपाल और रायसेन जिले की कोर ग्रुप एवं जिला बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संगठन की व्यापकता और जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सक्रियता जरूरी है। कार्यकर्ता समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर जनसमस्याओं को समझें और सेवा कार्यों के माध्यम से विश्वास अर्जित करें। चंद्रशेखर ने कहा कि नियमित संगठनात्मक प्रवास, प्रभावी जनसंपर्क और आपसी समन्वय से संगठन मजबूत होता है। भाजपा की शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ताओं में निहित है। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ निभानी चाहिए। संगठन का विस्तार केवल औपचारिक गतिविधियों से नहीं, बल्कि जनता के बीच निरंतर उपस्थिति और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता से संभव है। उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करने और संगठनात्मक कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सामाजिक विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के साथ पार्टी की नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचानी चाहिए। बैठक में पार्टी की पूर्ण हो चुकी गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर



भी चर्चा की गई। भोपाल की बैठक में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय, जिला प्रभारी जसवंत सिंह हाड़ा तथा पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह उपस्थित रहे। रायसेन की बैठक में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, प्रदेश मंत्री राजो मालवीय, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक सुरेंद्र पटवा, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। रविंद्र यति और रायसेन जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी।

संपादकीय

स्टारलिंक और भारत की रणनीतिक चिंताएँ

एलन मस्क की तरफ से भारत में स्टारलिंक की शुरूआत में हो रही देरी पर आलोचना ने उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं के नियमन को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यह बहस केवल किसी निजी कंपनी को भारतीय बाजार में प्रवेश देने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और संचार व्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण जैसे गंभीर प्रश्न जुड़े हैं। भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधता वाले देश में उपग्रह इंटरनेट डिजिटल विभाजन को कम करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है लेकिन इसके साथ जुड़े सुरक्षा जोखिमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

स्टारलिंक जैसी सेवाएँ पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं। इनकी सहायता से दूरस्थ गाँवों, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों और सीमावर्ती इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुँचाई जा सकती है, जहाँ पारंपरिक दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करना कठिन और महँगा होता है। हालाँकि, इन सेवाओं की वैश्विक प्रकृति, पोर्टेबल टर्मिनलों और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता के कारण नियामक संस्थाओं के सामने नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।

सबसे प्रमुख चुनौती आतंकवादी गतिविधियों में संभावित दुरुपयोग की है। दूरदराज के क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी संगठन या अन्य गैर-राज्यीय तत्व उपग्रह संचार प्रणालियों का उपयोग अपनी गतिविधियों के समन्वय के लिए कर सकते हैं। मणिपुर में वर्ष 2024 के दौरान स्टारलिंक-ब्रांडेड उपकरण मिलने की खबरों ने इस आशंका को चर्चा में ला दिया था। हालाँकि, किसी उपकरण की बरामदगी अपने आप में उसके वास्तविक उपयोग या किसी संगठन से उसके संबंध का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसलिए सुरक्षा आकलन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं और तकनीकी जाँच पर आधारित होना चाहिए।

दूसरी चुनौती सीमा पार अपराध और तस्करी से संबंधित है। भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ, विस्तृत समुद्री क्षेत्र और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं। यदि उपग्रह इंटरनेट टर्मिनलों का उपयोग अवैध गतिविधियों के समन्वय में किया जाता है तो अपराधियों की पहचान और उनके संचार की जाँच कठिन हो सकती है। अंडमान क्षेत्र में वर्ष 2024 में मादक पदार्थों की बरामदगी के संदर्भ में स्टारलिंक उपकरणों की चर्चा भी हुई थी। ऐसे मामलों में उपकरणों की वास्तविक भूमिका की पुष्टि आवश्यक है क्योंकि केवल उनकी मौजूदगी से तस्करी और उपग्रह नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध नहीं होता।

तीसरी चुनौती डेटा संप्रभुता और विदेशी नियंत्रण की है। उपग्रह नेटवर्क का संचालन, तकनीकी प्रबंधन और डेटा-संबंधी कुछ प्रक्रियाएँ भारत से बाहर नियंत्रित हो सकती हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि भारतीय उपयोगकताओं के संचार संबंधी आँकड़ों पर किसका नियंत्रण होगा, उनका प्रसंस्करण कहाँ किया जाएगा और भारतीय कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं तक पहुँच कैसे सुनिश्चित होगी। यदि इन विषयों पर स्पष्ट नियम नहीं होंगे तो जाँच एजेंसियों और नियामकों के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रभावी प्रयोग कठिन हो सकता है।

चौथी चुनौती वैध निगरानी और कानून प्रवर्तन की है। पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्क में सेवा प्रदाताओं, लाइसेंसिंग शर्तों और घरेलू नेटवर्क अवसंरचना के माध्यम से कानूनी निगरानी की व्यवस्था लागू की जा सकती है। उपग्रह इंटरनेट में विदेशी नेटवर्क संचालन और सीमा-पार डेटा प्रवाह के कारण इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी क्षमता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। यदि सेवा प्रदाता भारतीय कानूनों के अनुरूप वैध आदेशों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं, तो आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध की जाँच प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, निगरानी की शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट कानून, आवश्यकतानुपात और जवाबदेही के अधीन होना चाहिए, ताकि नागरिकों की निजता और मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। पाँचवीं चुनौती रणनीतिक निर्भरता की है। यूक्रेन युद्ध के दौरान स्टारलिंक की भूमिका ने प्रदर्शित किया कि निजी उपग्रह संचार प्रणालियाँ संकट और युद्ध के समय अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं।

बच्चों के हित इंटरनेट उपयोग : न्यायालय का सुझाव और देश का हित !

डॉ. निवेदिता शर्मा

> पूर्ण प्रतिबंध या पूर्ण अनियंत्रण दोनों ही खतरनाक हैं। भारत को अपने युवा जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित डिजिटल नागरिकों में बदलने के लिए इस संतुलित रास्ते पर चलना चाहिए। वैश्विक तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि जिम्मेदार डिजिटल बचपन ही भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता और समृद्धि की नींव है, इसलिए यह आज अत्यधिक आवश्यक हो गया है कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने जो सुझाव दिया है कि बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल से पूरी तरह रोकने के बजाय सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए चाइल्ड मोड जैसे उपाय अपनाकर उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की 2026 की बेंच (जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन) ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट तक पहुंच और उसके उपयोग का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 19(1)(ए) के तहत प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को उनकी उम्र के बावजूद ये अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें पूरी तरह वंचित करना उतना ही बेतुका होगा जितना यह कहना कि छोटे बच्चों में कोई चेतना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। सुरक्षा और स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

न्यायालय ने पूर्ण प्रतिबंध के बजाय चाइल्ड मोड, मजबूत सीएसईएएम (बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री) पहचान-हटाने की व्यवस्था, माता-पिता की सहमति और निजी प्रोफाइल जैसे उपाय सुझाए। यह निर्णय अनुराधा भसीन (2020) और प्रज्ञा प्रसून (2025) जैसे पूर्व निर्णयों की पृष्ठभूमि में आया है। यहां उपयोगकर्ता के एंगल से यह बात महत्वपूर्ण है कि यदि बच्चों के हित में इंटरनेट के सीमित या नियंत्रित उपयोग का सुझाव सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो जाए, तब भी यह देश के उज्ज्वल भविष्य के हित में हो सकता है। पूर्ण प्रतिबंध नकारात्मक हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार, आयु-उपयुक्त और सुरक्षा-केंद्रित पहुंच भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश, शिक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

वैसे यह सच है कि 2025-2026 में दुनिया भर में बच्चों के सोशल मीडिया और इंटरनेट उपयोग पर प्रतिबंधों की लहर आई है। ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खाते बनाने पर प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बना। प्लेटफॉर्म्स को उम्र सत्यापन के उचित कदम उठाने होंगे, अन्यथा भारी जुमार्ना। यूनाइटेड किंगडम ने जून 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के लिए समान प्रतिबंध की घोषणा की, जोकि 2027 तक लागू होने की संभावना है। यूरोपीय संघ का Kids Act प्रस्ताव 13 वर्ष से कम पर पूर्ण प्रतिबंध और 15 वर्ष से कम पर सीमित खातों की बात करता है। इंडोनेशिया (16 वर्ष), मलेशिया (16 वर्ष), ब्राजील, यूएई (15 वर्ष) और अन्य देशों ने भी विभिन्न रूपों में आयु सीमा लागू या प्रस्तावित की है। चीन में माइनर मोड के जरिए स्क्रीन टाइम और ऐप-विशिष्ट प्रतिबंध पहले से ही उपयोग में लिया जा रहा है। इन उठाए गए तमाम कदमों को देखने पर पता चलता है कि ये सभी कदम मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिंग, लत और यौन शोषण की चिंताओं से प्रेरित हैं।

भारत में डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ी है, लेकिन उपयोग और कौशल में बड़ी खाई है। अरएफ2024 के अनुसार, 14-16 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में से लगभग 90 प्रतिशत के घर में स्मार्टफोन है और 82 प्रतिशत उपयोग करना जानते हैं, लेकिन केवल 57फीसद शैक्षिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि 76फीसद सोशल मीडिया के लिए। व्यक्तिगत स्वामित्व लड़कों (36%) में लड़कियों (27%) से अधिक है। स्कूलों में स्थिति और खराब है, यहां लगभग 25-64 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में कार्यात्मक कंप्यूटर और इंटरनेट है, राज्यवार भारी असमानता है। NSSO और अन्य सर्वेक्षण बताते हैं कि युवाओं में बेसिक इंटरनेट कौशल (सर्च, ईमेल, ट्रांजैक्शन) केवल 25-30 फीसद के आसपास है, ग्रामीण महिलाओं में और कम प्रतिशत में यह देखने को मिलता है। DPDP Act 2023 में 18 वर्ष से कम को बच्चा माना गया है और उनके डेटा प्रोसेसिंग के लिए सत्यापित माता-पिता की सहमति अनिवार्य है (नियम 2027 से पूर्ण लागू होने की संभावना)। यह वैश्विक मानकों से अधिक सख्त है, जहां अक्सर 13-16 वर्ष की सीमा है। भारत का AadharDigiLocker सिस्टम उम्र सत्यापन के लिए उपयोगी है, हमारे यहां 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे हैं और ये सभी बाल अधिकार संरक्षण देखरेख के अंतर्गत आते हैं।

भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है। हम ये मानते भी हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई, स्टार्टअप और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए डिजिटल रूप से साक्षर पीढ़ी जरूरी है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के लिए यह अपरिहार्य भी है, किंतु इस कारण से हम अपने बच्चों को खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं कि वह जो चाहें वह देखें और समझें, इसलिए समझदारी बेहद जरूरी है। ऐसे में अभी सामने आया सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण भारत के हित में है। पूर्ण प्रतिबंध ह्नअसिद्ध उपायों की सिद्ध असंगतिह्व है, जैसा अदालत ने कहा। वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू करना कठिन है और अनियमित स्थानों को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी ओर, चाइल्ड मोड, डिफॉल्ट प्राइवेट प्रोफाइल, अज्ञात वयस्कों से संदेश प्रतिबंध, मजबूत सामग्री मॉडरेशन और सीएसईएएम हटाने की तेज व्यवस्था बच्चों को सुरक्षित रखते हुए पहुंच बनाए रखती है।

वैश्विक साक्ष्य दिखाते हैं कि समस्या कितना समय से अधिक क्या सामग्री और कैसे उपयोग की है, इससे ही आज सबसे अधिक पैदा हो रही है, इसलिए पूर्ण प्रतिबंध के बजाय स्मार्ट रेगुलेशन, जैसेकि ऑस्ट्रेलिया मॉडल का संशोधित रूप, यूरोपीय safety-by-design और भारत के डीपीडीपी ढांचे का प्रभावी क्रियान्वयन बेहतर है। कुल मिलाकर कहें तो यही कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संवैधानिक रूप से सही और व्यावहारिक रूप से विवेकपूर्ण है। बच्चों की सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए अनिवार्य है। यदि नियंत्रित, सुरक्षित और कौशल-उन्मुख इंटरनेट पहुंच सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो जाए तो यह न केवल बच्चों के हित में है, बल्कि देश की शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के हित में भी है।

पूर्ण प्रतिबंध या पूर्ण अनियंत्रण दोनों ही खतरनाक हैं। भारत को अपने युवा जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित डिजिटल नागरिकों में बदलने के लिए इस संतुलित रास्ते पर चलना चाहिए। वैश्विक तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि जिम्मेदार डिजिटल बचपन ही भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता और समृद्धि की नींव है, इसलिए यह आज अत्यधिक आवश्यक हो गया है कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने जो सुझाव दिया है कि बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल से पूरी तरह रोकने के बजाय सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए चाइल्ड मोड जैसे उपाय अपनाकर उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। वह वास्तव में सही प्रतीत होता है।

एसआईआर पर संग्राम, कांग्रेस की चुनावी हार पर सवाल

विवेक शुक्ला

कभी देश के बड़े हिस्से में सरकार बनाने वाली कांग्रेस आज कई राज्यों में कमजोर स्थिति में है। तमिलनाडु में कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री बने छह दशक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी वह लंबे समय से सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच सकी है। गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों में भी उसे लंबे समय से सत्ता से बाहर रहना पड़ा है। इन राज्यों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। कहीं क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है तो कहीं भाजपा ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की है। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह इन बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपना संगठन और नेतृत्व तैयार करे। केवल पुराने राजनीतिक गौरव के सहारे जनता का भरोसा वापस नहीं पाया जा सकता।



ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। इसके लिए राजनीतिक दलों को लोगों के बीच जाना होता है, उनकी समस्याएं समझनी होती हैं और अपनी नीतियों पर भरोसा पैदा करना होता है। लेकिन जब कोई पार्टी लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना करती है, तो उसके सामने आत्ममंथन का सवाल भी खड़ा होता है। कांग्रेस आज इसी स्थिति से गुजर रही है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं बल्कि चुनाव आयोग चुनाव जितवा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की दशकों पुरानी चुनावी गिरावट के लिए केवल चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

राहुल गांधी के आरोपों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक निशाने पर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम कर रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है लेकिन गंभीर आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण भी होने चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी से किसी आरोप की सत्यता साबित नहीं होती। भाजपा की ओर से कांग्रेस को जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उसके चुनावी इतिहास का हवाला दिया। उनका सवाल था कि यदि चुनाव आयोग और एसआईआर ही कांग्रेस की पराजय के कारण हैं तो उन राज्यों में पार्टी की कमजोरी का क्या कारण है, जहां वह लंबे समय से सत्ता से बाहर है?

अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग सवाल उठाए। जयराम रमेश ने पूछा कि कितने घुसपैठियों की पहचान हुई और कितनों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए या उन्हें देश से बाहर निकाला गया। पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती पर सवाल खड़ा किया। के.सी. वेणुगोपाल ने शाह के बयान को अगले चुनाव के परिणाम की अग्रिम घोषणा बताते हुए भाजपा पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया।

इन प्रतिक्रियाओं के बीच कांग्रेस की चुनावी गिरावट पर बहस पीछे छूट गई। एसआईआर और घुसपैठियों से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस को अपनी राजनीतिक कमजोरियों पर भी विचार करना चाहिए। अमित शाह का मुख्य तर्क यही था कि पार्टी अपनी हार के कारणों की समीक्षा करे।

कांग्रेस को लोकसभा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिले चार दशक से अधिक समय बीत चुका है। वर्ष 1984 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों में पार्टी ने 543 निर्वाचित सीटों में से 404 सीटें जीती थीं। उसके बाद कांग्रेस कभी अपने दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी।

राजीव गांधी के नेतृत्व में पार्टी 1989 और 1991 के चुनावों में भी बहुमत से दूर रही। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2004 और 2009 में वापसी की। 2004 में उसने 145 और 2009 में 206 सीटें जीतीं। सहयोगियों के साथ केंद्र में सरकार भी बनाई। लेकिन इसके बाद पार्टी का प्रदर्शन तेजी से गिरा।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में उसे 52 सीटें मिलीं, जबकि 2024 में उसकी सीटें बढ़कर 99 हो गईं। यह सुधार जरूर था लेकिन पार्टी बहुमत से बहुत दूर रही। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कांग्रेस की चुनावी चुनौतियां एसआईआर से बहुत पुरानी हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को उसकी दशकों की राजनीतिक गिरावट का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता।

कभी देश के बड़े हिस्से में सरकार बनाने वाली कांग्रेस आज कई राज्यों में कमजोर स्थिति में है। तमिलनाडु में कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री बने छह दशक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी वह लंबे समय से सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच सकी है। गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों में भी उसे लंबे समय से सत्ता से बाहर रहना पड़ा है।

इन राज्यों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। कहीं क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है तो कहीं भाजपा ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की है। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह इन बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपना संगठन और नेतृत्व तैयार करे। केवल पुराने राजनीतिक गौरव के सहारे जनता का भरोसा वापस नहीं पाया जा सकता।

राजनीतिक विश्लेषक बिक्रम उपाध्याय मानते हैं कि अमित शाह ने कांग्रेस को यह सही नसीहत दी कि दिल्ली में कुछ हजार लोगों की भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। राजनीतिक दलों को गांवों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना पड़ता है। जनता की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए काम करना जरूरी है। यह बात कांग्रेस ही नहीं, हर राजनीतिक दल पर लागू होती है। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाना भी विपक्ष का अधिकार है। लेकिन विरोध के साथ संगठन मजबूत करना और जनता के बीच लगातार काम करना भी जरूरी है।

कांग्रेस की चुनौती यह है कि वह अपनी चुनावी पराजयों की जिम्मेदारी तय करे। क्या पार्टी का संगठन कमजोर हुआ है? क्या उसका नेतृत्व लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है? क्या उसकी नीतियां नए मतदाताओं को आकर्षित कर पा रही हैं? इन सवालों पर गंभीर चर्चा के बिना राजनीतिक वापसी कठिन होगी। भाजपा हाल के स्थानीय निकाय और ग्राम समिति चुनावों में अपने प्रदर्शन को जनता के समर्थन के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस को भी इन नतीजों और अपने प्रदर्शन का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। हर चुनाव के परिणाम को उसके स्थानीय और राजनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी है।

राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणों के साथ सामने रखना। दूसरी, अपनी चुनावी कमजोरियों को स्वीकार कर संगठन में सुधार करना। ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। लोकतंत्र में किसी भी दल को जीत का स्थायी अधिकार नहीं मिलता। जनता का विश्वास कामकाज, नेतृत्व और नीतियों से अर्जित करना पड़ता है। कांग्रेस यदि अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहती है तो उसे आरोपों से आगे बढ़कर आत्ममंथन करना होगा। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना एक राजनीतिक विकल्प हो सकता है लेकिन अपनी कमजोरियों को दूर करना उसकी जरूरत है।

न्यूज ब्रीफ

ग्वालियर में गड्ढों से मिलेगी राहत, कोर्ट के निर्देश पर सर्वे रिपोर्ट पेश

ग्वालियर। शहर की सड़कों की गुणवत्ता और गड्ढों की मरम्मत से जुड़े मामलों को लेकर शुक्रवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (ह्यादृढ़) ने अदालत के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए नेटवर्क सर्वे व्हीकल (ह्यस्ङ्क) के माध्यम से कराए गए सड़क सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की। वहीं, दूसरी ओर ग्वालियर नगर निगम ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर किए गए पेचवर्क (गड्ढे भरने के कार्य) की विस्तृत जानकारी अदालत को सौंपी।पूर्व की सुनवाई के दौरान अदालत में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि ह्यादृढ़ के अंतर्गत आने वाली सड़कों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने प्राधिकरण को पिछले सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, ताकि सड़कों की मौजूदा स्थिति और तकनीकी मानकों के पालन का सही आकलन किया जा सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर अब अदालत सड़कों की वास्तविक गुणवत्ता की समीक्षा करेगी।

शातिर चोर को पुलिस ने चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार

ग्वालियर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह, भापुसे द्वारा चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाकर चोरों को पकड़ने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादी अंकित गर्ग निवासी बिजय ट्रेडिंग के सामने दाल बाजार लश्कर ग्वालियर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लेख कराई कि वह रोजाना की तरह दिनांक 14.10.2026 को करीब रात के 09.00 बजे अपनी किराना शोप में ताला लगाकर अपने घर चला गया था। जब दिनांक 15.10.2026 को सुबह अपनी दुकान पर आया तो मेरी दुकान के दोनो गेट खिचे हुये थे उसके अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे गल्ले मे रखे करीब 4300 रुपये व दो चाँदी के सिक्के मैंने देखे तो नहीं मिले इसी दौरान मेरे पडोस में बिजय मित्तल की किराने की दुकान श्रीनाथ ट्रेडर्स के बाहर एक काउन्टर रखा था उसमे करीब 150-200 रुपये रखे थे उस काउंटर की दराज को तोड़कर रूपये निकाल के ले गया है व उसी के पास कौशल हविलानी के गोदाम का भी ताला तोड़ कर चले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अप0क्र0 140/26 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषानुसार सीएसपी लष्कर श्रीमती किरण अहिरवार के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक विनोद विनायक करकरे के द्वारा थाना बल की टीम को उक्त चोरी का खुलासा कर आरोपी को शीध्र पकड़ने हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना आज दिनांक 17.10.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर से उक्त प्रकरण में एक संदेही को माढरें की माता आर्यवेदिक कॉलेज टंकी के पास से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शिवम उर्फ कालिया पुत्र कल्लू बंषकार उम्र 19 साल निवासी केंसर पहाडिया गड्ढा हाल मोहल्ला जिला ग्वालियर होना बताया। पकड़े गये संदेही से उक्त प्रकरण के संबंध में गहनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त अपराध कारित करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा पकड़े गये आरोपी के कब्जे से दो चांदी के सिक्के एवं 2000/- रूपये नगद विधिवत जप्त किये गये पूछताछ में आरोपी द्वारा शेष रूपये खर्च करना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी को थाना कोतवाली के अपराध सदर में विधिवत गिरफ्तार किया गया।

पुलिसकर्मी सोते रहे हथकड़ी सहित फरार हो गया चोर

ग्वालियर। छतरपुर में चोरी करने का आरोपी सन्नी ग्वालियर में पुलिस कस्टडी से हथकड़ी सहित फरार हो गया। पुलिसकर्मी इलाज कराने के लिए उसे ग्वालियर लाए थे। रात में इलाज नहीं हुआ तो थाने के स्थान पर पुलिसकर्मी आरोपी को अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गए और वहीं रात्रि विश्राम किया। मौका मिलते ही आरोपी हथकड़ी सहित भाग गया। आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। रिश्तेदार के फ्लैट पर सोने से पहले पुलिसकर्मियों ने होटल में पार्टी भी की। सीएसपी विश्वविद्यालय रवि भदौरिया के मुताबिक, छतरपुर पुलिस में पदस्थ आरक्षक विजय यादव, शुभम शर्मा और संदीप चोरी के आरोप में पकड़े गए बंदी सन्नी पाल (30), निवासी उत्तराखंड, को हाथ में चोट के इलाज के लिए ग्वालियर लाए थे।

ग्वालियर नगर निगम परिसर में सामने आया मामला, अपर आयुक्त ने दिए जांच के निर्देश

फिल्म की शूटिंग के लिए जलकुंड खाली करने का आरोप
जल-विहार में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से मचा हड़कंप

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।



ग्वालियर नगर निगम परिषद के जल-विहार परिसर में बने जलकुंड में बड़ी संख्या में मछलियां मृत मिलने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम में हलचल मच गई है। जिस जलकुंड में कुछ समय पहले तक मछलियां तैरती दिखाई देती थीं और जिन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते थे, वहां अब मछलियां मृत अवस्था में मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रारंभिक तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि दो दिन पहले फिल्म की शूटिंग के लिए परिसर में अनुमति दी गई थी और शूटिंग के दौरान जलकुंड का पानी खाली कर मछलियों को बाहर निकाला गया। आशंका जताई जा रही है कि पानी की कमी के कारण मछलियों की मौत हुई होगी। हालांकि, मछलियों की मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर आयुक्त मुनीश सिकरवार ने शनिवार को जांच के निर्देश दिए हैं। अब जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जल-विहार परिसर में फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति किस स्तर से दी गई थी, शूटिंग के दौरान जलकुंड में क्या गतिविधियां हुईं और मछलियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि जलकुंड में पानी कम होने या उसे खाली किए जाने की स्थिति में मछलियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और किसी व्यक्ति या अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शूटिंग के लिए औपचारिक अनुमति किस अधिकारी या कार्यालय ने जारी की थी। अनुमति किन शर्तों पर दी गई थी और क्या उसमें जलकुंड के पानी अथवा वहां मौजूद मछलियों से संबंधित किसी गतिविधि की मंजूरी शामिल थी, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें शूटिंग के दौरान की गई सभी गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं थी। ऐसे में अनुमति से जुड़े दस्तावेजों और शूटिंग के दौरान हुई गतिविधियों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जलकुंड में मृत मिलीं मछलियां, उठे सवाल

जल-विहार के जलकुंड में बड़ी संख्या में मछलियों के मृत मिलने से परिसर की व्यवस्था और जलीय जीवों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जलकुंड में मछलियों का होना परिसर के वातावरण और उसकी पहचान का हिस्सा रहा है। यहां आने वाले लोग मछलियों को तैरते हुए देखते थे, लेकिन अब उनके मृत मिलने की घटना ने लोगों को चिंतित कर दिया है। यदि शूटिंग के दौरान जलकुंड का पानी खाली किया गया था, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय होगा कि ऐसा किस उद्देश्य से किया गया और इस प्रक्रिया में मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए। पानी की कमी मछलियों की मौत की संभावित वजह बताई जा रही है, लेकिन केवल इसी आधार पर मौत का कारण तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए जलकुंड की स्थिति, पानी की उपलब्धता और अन्य परिस्थितियों की जांच आवश्यक होगी। इस मामले में यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि शूटिंग के दौरान जलकुंड में मौजूद मछलियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोई व्यवस्था की गई थी या नहीं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय करना भी जांच का अहम हिस्सा होगा। अपर्णा पाटिल ने कहा- दोषियों पर हो कार्रवाई भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने जल-विहार के जलकुंड में बड़ी संख्या में मछलियों के मृत मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पहले जलकुंड में मछलियां तैरती दिखाई देती थीं और उन्हें देखने के लिए लोग आते थे। अब वहां बड़ी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में पड़ी मिलना बेहद दुखद है।

शूटिंग की अनुमति मिलने की बात कहकर पहुंचे थे लोग

जल-विहार परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार, कुछ लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंचे थे। कर्मचारियों को पार्क प्रभारी बंसल का नाम भी बताया गया था। इस जानकारी के बाद शूटिंग की अनुमति से जुड़े मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि मछलियों की मौत की वास्तविक वजह सामने आ सके।

ज्यादा ब्याज से परेशान होकर मंदिर में खाई कसम हिसाब के बहाने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी हत्या

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

झांसी रोड स्थित केदारपुर में पुरुषोत्तम गुर्जर की हत्या करने से पहले चारों आरोपित सुबह शीतला माता मदिर पहुंचे थे। यहां हत्या की कसम खाई। पुजारी से आशीर्वाद लिया और मां की प्रतिमा पर चढ़ी माला मांगी कि काम सफल हो। यही माला पहनकर आरोपित पहुंचे और रात पुरुषोत्तम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने 72 घंटे में इस हत्या कांड का राजफाश कर दिया। पूछताछ में चारों आरोपित ने बताया कि पुरुषोत्तम से रुपये उधार लिए थे। वह 20 प्रतिशत ब्याज वसूलता था। मूल से ज्यादा ब्याज चुके थे। फिर भी वह रुपये मांग रहा था। तंग आकर उसकी हत्या कर दी। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि झांसी रोड में हत्या के मामले का 72 घंटे में राजफाश कर दिया है। चार आरोपित पकड़े गए हैं। ब्याज को लेकर अनबन थी, जिसके चलते हत्या हुई है। 14 अक्टूबर 2026 को डायल 112 पर सूचना मिली थी कि भागीरथ गुर्जर के खेत में एक शव पड़ा हुआ है। मृतक की शिनाख्त पुरुषोत्तम गुर्जर (35 वर्ष) निवासी छोटी मडईयां, केदारपुर के रूप में हुई। उसके सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए गए थे। पुलिस को पता लगा था कि पुरुषोत्तम ब्याज पर रुपये उधार देता था। रात को भी उसकी फोन पर किसी से बहस हुई थी। ग्राम छोटी मडईयां निवासी रमन गुर्जर, राधाकृष्ण गुर्जर, छोटू उर्फ राहुल गुर्जर और विजय उर्फ खैरी गुर्जर ने उससे करीब 20 प्रतिशत ब्याज की भारी दर पर लाखों रुपये का कर्ज ले रखा था। मृतक मूल रकम से ज्यादा ब्याज वसूल चुका था। इसके बाद भी मूल रकम मांग रहा था। इसी से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। घटना से तीन दिन पहले सभी आरोपितों ने मिलकर पुरुषोत्तम को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, इसलिए 13 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11 बजे आरोपित रमन गुर्जर ने पुरुषोत्तम को घर के बाहर सोते समय उठाया। वह उसे पैसे देने और हिसाब करने के बहाने भागीरथ के खेत में ले गया। वहां पहले से मौजूद अन्य आरोपितों ने बातचीत के दौरान अचानक कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर पुरुषोत्तम की हत्या कर दी। पुलिस को लाश के पास से एक पर्ची मिली थी। जिसमें 3.32 लाख रुपये का हिसाब था।



पुरुषोत्तम गुर्जर

सिकंदर कंपू और कंपू क्षेत्र में जब्त की अंग्रेजी व देसी शराब

ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई 11 प्रकरण दर्ज

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं संभागीय आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के आदेशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत सिकंदर कंपू, हजीरा, बिरला नगर कॉलोनी, चक केशवपुर गांव और डबरा क्षेत्र में दबिश देकर अवैध मदिरा जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 11 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत दर्ज किए गए। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 35 हजार रुपये बताई गई है।

सिकंदर कंपू क्षेत्र में बेटी बचाओ चौराहे के पास तिलक नगर में चंद्रकांत काले के रिहायशी मकान से विभिन्न ब्रांड की 12 बल्क लीटर अंग्रेजी मदिरा जब्त की गई। वहीं, कंपू क्षेत्र में पानी की टंकी के पीछे सूरज कुशवाह से 13 पाव और सुनील उर्फ सनी कुशवाह से 11 पाव देसी मदिरा प्लेन जब्त की गई। संबंधित मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। जब्त मदिरा के नमूने लेकर भौतिक परीक्षण और ईएएल स्कैन की प्रक्रिया भी पूरी की गई। बिरला नगर की सब्जी मंडी क्षेत्र से 25 पाव देसी मदिरा प्लेन जब्त की गई। इसी क्षेत्र में बालाजी डेयरी से सौरभ शिवहरे के आधिपत्य से 15 पाव देसी मदिरा प्लेन और 5 लीटर बोल्ट बीयर बरामद की गई। चक केशवपुर गांव में महेंद्र कुशवाह के मकान से 14 पाव देसी मदिरा मसाला जब्त की गई। इन मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। डबरा में 1100 किलोग्राम गुड़ लाहन नष्ट डबरा क्षेत्र के गुंजार कंजर डेरा में दबिश के दौरान तीन ड्रमों में लगभग 1100 किलोग्राम गुड़ लाहन बरामद किया गया।

ग्वालियर व्यापार मेले में ऑनलाइन होगा दुकानों का आवंटन, 9 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला वर्ष 2026-27 में दुकानों का आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा। मेले का आयोजन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगा। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। जिन दुकानदारों को पोर्टल पर अपनी दुकान प्रदर्शित नहीं होने या आवंटन संबंधी कोई समस्या है, वे 31 अक्टूबर 2026 तक मेला कार्यालय में आवेदन देकर उसका निराकरण करा सकते हैं। मेला प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रथम चरण में ऑटोमोबाइल सेक्टर, झूला सेक्टर और पक्की दुकानों के लिए आवेदन एवं आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन दुकानों के लिए नियमानुसार आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। द्वितीय चरण में अस्थायी टीन की दुकानों, चबूतरा सेक्टर, सी सेक्टर, एसटी सेक्टर और एनएससी सेक्टर सहित अन्य सेक्टर की शेष दुकानों के लिए 17 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। मेला सचिव ने बताया कि वर्ष 2024-25 तक आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल दुकानदारों और व्यापारियों को वर्ष 2026-27 के मेले के लिए पात्र माना गया है। कई वर्षों से मेले में दुकान लगाने वाले कुछ दुकानदारों और व्यापारियों की दुकानें ऑनलाइन प्रक्रिया में अभी प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। ऐसे दुकानदारों और व्यापारियों को अपनी दुकान की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

घर से नाराज होकर गई दो गुमषुदा बालिकाओं को आरोन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ग्वालियर से सकुशल किया दस्तयाब

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुमशुदा नाबालिग बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देषों के अनुक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री जयराज कुबेर द्वारा अपने अधीनस्थ सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र से गुमशुदा नाबालिग बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। घटनाओं का संक्षिप्त विवरण (1) फरियादी मोहन(परिवर्तित नाम) निवासी आरोन थाना आरोन जिला ग्वालियर ने थाना आरोन में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14.10.2026 को दोपहर करीब 12.00 बजे उसकी लड़की नेहा(परिवर्तित नाम) उम्र 17 साल 08 माह घर से बिना बताये कही चली गई और काफी देर तक नही लौटी तो सभी लोनो ने उसकी तलाश गाँव मे तथा आस पास और अपने नजदीकी रिश्तेदारी मे की, कही कोई जानकारी नही मिली। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना आरोन में अप0क्र0-68/26 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया। (2) फरियादी रमेष(परिवर्तित नाम) निवासी आरोन जिला ग्वालियर ने थाना आरोन में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14.10.26 को दोपहर के समय उसकी भांजी सीमा(परिवर्तित नाम) उम्र 18 साल 10 माह निवासी मुरैना हाल निवासी आरोन घर से बिना बताए कहीं चली गई और काफी देर तक नही लौटी तो सभी लोगों ने उसकी तलाश गाँव में तथा आसपास और अपने नजदीकी रिश्तेदारी में की, कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना आरोन में अप0क्र0-69/26 धारा 140(3) बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया।

17वें भव्य रामलीला समारोह में अशोक वाटिका और लंका दहन की लीला का मनमोहक मंचन

अशोक वाटिका उजाड़ी, हनुमान जी ने किया लंका दहन, जय श्रीराम के नारों से गूंजा रामलीला मैदान

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

दीनदयाल नगर, सेक्टर-सी में आयोजित 17वें भव्य रामलीला समारोह में शनिवार को सप्तम दिवस पर अशोक वाटिका और लंका दहन की लीला का भव्य एवं मनमोहक मंचन किया गया। कानपुर और अयोध्या से आए कलाकारों ने अपनी सशक्त अभिनय कला के माध्यम से रामायण के इस महत्वपूर्ण प्रसंग को जीवंत कर दिया। हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, उनकी बुद्धिमत्ता और प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति का मंचन देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। जैसे ही लंका दहन के दृश्य का मंचन हुआ, पूरा रामलीला मैदान जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। दर्शकों ने उत्साह के साथ भगवान श्रीराम और हनुमान जी के जयकारे लगाए। रामलीला की शुरुआत प्रभु श्रीराम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका पहुंचे हनुमान जी के प्रसंग से हुई। मंचन में दिखाया गया कि माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं। रास्ते में उनका सामना सुरसा और लंकिनी से होता है। हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और पराक्रम से सभी बाधाओं को पार करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। इसके बाद वे माता सीता की खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां माता सीता प्रभु श्रीराम की माता सीता को दी



प्रभु श्रीराम की मुद्रिका अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्रीराम की मुद्रिका देकर उनके आगमन का संदेश सुनाया। मुद्रिका देखकर माता सीता को विश्वास हुआ कि हनुमान जी वास्तव में प्रभु श्रीराम के दूत हैं। हनुमान जी ने माता सीता को भरोसा दिलाया कि प्रभु श्रीराम शीघ्र ही लंका पहुंचकर रावण के अत्याचारों का अंत करेंगे और उन्हें उसके बंधन से मुक्त कराएंगे। इस भावुक प्रसंग का मंचन देखकर दर्शकों ने प्रभु श्रीराम के प्रति माता सीता की अटूट आस्था और हनुमान जी की निष्ठा को अनुभव किया। इसके बाद रामलीला में हनुमान जी के पराक्रम का रोमांचक प्रसंग दिखाया गया। माता सीता से भेंट करने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में फल खाए और वहां के वृक्षों को उजाड़ दिया। वाटिका की सुरक्षा में तैनात राक्षसों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उनका सामना करते हुए अपने अद्भुत बल का परिचय दिया। इस दौरान रावण के सैनिकों के साथ हुए युद्ध और रावण पुत्र अक्षय कुमार के वध का मंचन भी किया गया। इन दृश्यों ने रामलीला मैदान में मौजूद दर्शकों में विशेष उत्साह भर दिया। अशोक वाटिका में हनुमान जी के पराक्रम और राक्षसों के पराजित होने की सूचना रावण तक पहुंची। इसके बाद रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए अपने योद्धाओं को भेजा। मंचन में दिखाया गया कि मेघनाद ने हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। रावण के दरबार में हनुमान जी ने निर्भीक होकर प्रभु श्रीराम का संदेश सुनाया और रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लौटाने की सीख दी।उनकी निष्ठा का दृश्य दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहा।



नकुल धुल के एविक्शन पर एल्विश यादव ने दी प्रतिक्रिया

रियलिटी शो 'बिग बॉस-20' के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नकुल धुल (मिट्ठू डॉन) और गुल्लू (कुशल तंवर) के बीच तीखी हाथापाई हो गई। इसी पूरे ड्रामे पर अब यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी- 2 के विनर एल्विश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस शारीरिक हिंसा के बाद शो के नियमों के मुताबिक मेकर्स ने नकुल धुल को घर से बाहर निकाल दिया है। इसी पूरे मामले पर अब यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने नकुल को इंडायरेक्टली तंज कसा। एल्विश यादव ने लिखा, 'बहुत दिनों बाद आज बिग बॉस देखा। नियम बदल गए हैं, अब शायद जो भी घर में बड़े या समझदार की तरह रहता है उसे ही निकाल देते हैं। दुख हुआ देखकर।'

एल्विश यादव के इस कमेंट ने सोशल मीडिया पर टकराव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे दोनों के फैंस के बीच सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया है। जहां एक तरफ एल्विश यादव गुल्लू के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर रजत दलाल और लक्ष्य चौधरी जैसे बड़े नाम इस लड़ाई में नकुल धुल के गेमप्ले और उनके इम्पैक्ट का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, काजी तौकीर ने स्काउट ओपी के बारे में कुछ कहा था, जिसे लेकर नकुल धुल ने स्काउट के सामने यह बात उठाई। जब काजी और स्काउट के बीच बहस हो रही थी, तब गुल्लू (कुशल तंवर) बीच-बचाव करने और मामला शांत कराने पहुंचे। नकुल धुल इस बात पर भड़क गए कि गुल्लू उन्हें समझाने वाले कौन होते हैं। बहस इतनी बढ़ी कि नकुल और गुल्लू के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई हो गई। घर के सदस्यों के बीच-बचाव के बावजूद, फिजिकल वायलेंस (हिंसा) के नियमों के चलते बिग बॉस ने नकुल धुल को तुरंत घर से बाहर (बेघर) कर दिया।



राधिका मदान ने बताया कैसे खुद को ट्रोलिंग से बचाया

बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका मदान ने महिलाओं के लुक को लेकर दबाब झेलने पर बात की। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेलेब्स के लुक को ट्रोल करने पर भी काफी कुछ कहा। जानें क्या बोलीं राधिका...

बॉडी शेमिंग पर क्या बोलीं राधिका?

राधिका मदान ने बॉडी शेमिंग को लेकर अपना निजी संघर्ष भी साझा किया। उन्होंने बातचीत में कहा, 'मैंने फिल्म 'पटाखा' के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया था और 'शिद्दत' व 'अंग्रेजी मीडियम' के लिए मैं वह वजन घटा रही थी। इस दौरान मुझे कहा गया कि मैं बहुत मोटी हो गई हूं और हीरोइन कैसे बन सकती हूं? इसके बाद लगातार शूटिंग करते हुए मेरा वजन घटता रहा और मैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई।'

एक्ट्रेस ने खुद से किया यह सवाल

आगे अपने इंटरव्यू में राधिका ने कहा, 'मैंने खुद से पूछा कि मैं लोगों को खुश करने की कोशिश क्यों कर रही हूं, जबकि वे कभी खुश नहीं होंगे? इसलिए, मैंने एक खास शारीरिक बनावट पाने की चाहत के बजाय स्वास्थ्य रहने पर ध्यान देना शुरू किया। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो दूसरों की राय आपको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आप समझदार हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि उनकी आलोचना किस असुरक्षा से उपजी है। लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि अब मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही हूं।'

राधिका ने बताया कैसे करें खुद से प्यार?

अपनी बातचीत में राधिका मदान ने कहा, 'मुझे खुद से प्यार करने का विचार थोड़ा घिसा-पिटा लगता है, लेकिन आपको खुद को स्वीकार करना होगा। अपनी खूबियों के बारे में सोचना होगा। स्कूल के दिनों में मेरी भौहें जुड़ी हुई थीं और बहुत ज्यादा बाल थे। चूंकि मेरे माता-पिता का व्यवहार बहुत पॉजिटिव था, इसलिए मुझे इतना बढ़ावा दिया गया कि मुझे लगा कि लोगों को यह नहीं पता कि मैं कितनी सुंदर हूं। मेरे दोस्त थे, लेकिन मुझे कभी भी उनकी राय की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए, जब मेरी जुड़ी हुई भौहें हट गईं और लोग मुझे नोटिस करने लगे, तब भी मैंने उनमें बदलाव देखे।'



मां बनने के बाद काम पर लौटीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- बाउंस बैक जैसा कुछ नहीं होता

अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों पति विवेक दहिया के साथ कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद काम करने की चुनौतियों पर बात की। अभिनेत्री ने बताया कि बच्चों को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वे बड़े हो रहे हैं और अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी देखभाल का अनुभव भी बदल रहा है। दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, 'इस स्टेज पर बच्चों को संभालना आसान है, क्योंकि अभी बस वह सोते और खाते हैं लेकिन मुझे पता है कि अब उनके घुटनों के बल चलने का समय आएगा। उन्होंने धीरे-धीरे खुद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मेरे लिए तो उन्हें दो से चार मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना मुश्किल है। इसलिए मुझे उन्हें सेट पर भी साथ ले जाना पड़ता है। हालांकि, यह आसान नहीं है।'

अभिनेत्री ने बताया कि लोगों को इस बात पर भी हैरानी होती है कि वो इतनी जल्दी काम पर कैसे लौट आईं। उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा कहती हूं कि महिलाएं ऐसे ही 'बाउंस बैक' नहीं कर लेतीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही हम एक्ट्रेस कैमरे के सामने हंसती-मुस्कराती दिखती हैं लेकिन शरीर के अंदर दर्द, थकान और दिमाग में कन्फ्यूजन जैसा रहता है।' अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें काम पर लौटने की जरूरत नहीं थी लेकिन वे फिर भी लौटीं। क्योंकि एक मां के लिए घर पर बैठना भी आसान नहीं और काम करना भी आसान नहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मां बनने के बाद काम पर लौटने को लेकर महिलाओं की तुलना एक-दूसरे से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए महिलाओं को किसी और के अनुभव के दबाव में आने के बजाय अपनी जर्नी पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं ये इसलिए कह रही हूं ताकि कोई भी एक महिला की तुलना दूसरी से न करे और ये न कहे कि 'अरे दिव्यांका ने कर लिया।' नहीं, ये सबके लिए मुश्किल है। हर कोई अपने हिसाब से काम पर लौटता है। तो आप भी अपनी गति से चलें और मैं भी अपनी गति से चल रही हूं।'

महिला सशक्तिकरण और रूढ़ियों को तोड़ने पर कुब्रा सैत की बेबाक राय

अपनी बेबाक राय और बेझिझक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री कुब्रा सैत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में महिलाओं की आवाज बनने के लिए सम्मानित किए जाने पर महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी बात रखी। महिलाओं की ताकत और उनके संघर्ष करने की क्षमता को सिखाने की जरूरत वाली सोच पर सवाल उठाते हुए अभिनेत्री ने सशक्तिकरण और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी को लेकर एक नया नजरिया पेश किया है। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कुब्रा सैत ने कहा, ऐसे किसी भी मंच से जुड़ना, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि आज हालात बहुत खराब हैं और महिलाओं को मदद की जरूरत है। मेरा मानना है कि महिलाएं सदियों से साहसी और संघर्षशील रही हैं।

अगर कुछ है, तो वह यह कि हमने हमेशा अपने हक और अपनी इच्छाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। यह दर्ज किया गया हो या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं हम यह मानने लगे हैं कि यह पुरुषों की दुनिया रही है। हालांकि आपके पिछले पैनल में भी देखा कि किस तरह पुरुषों ने हमें वह महिला बनने का अवसर दिया, जो हम बनना चाहते हैं। और खासकर जब यह बात राजनीतिक स्तर पर कही जाती है, तो इसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। रही मेरी बात तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज बनने के लिए सम्मानित होना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। हालांकि, मुझे लगता है कि मुझे बस अपनी जिंदगी जीने, उसे पूरी तरह से अनुभव करने, गलतियां करने से न डरने और खुद के लिए एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि मैं एक महिला हूं। फिलहाल अपने इस दमदार बयान के साथ कुब्रा ने बातचीत को एक बार फिर व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि सशक्तिकरण केवल महिला होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी पसंद से जिंदगी जीने, फैसले लेने और अपने अनुभवों के जरिए खुद को समझने की आजादी से भी जुड़ा है।



सनी की फिल्म 'इक्का 2' की तैयारी हुई शुरू

सनी देओल की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'इक्का' के दूसरे पार्ट को लेकर नई जानकारी सामने आई है। फिल्म की कहानी लिखने का काम शुरू हो चुका है और इसके अगले साल आगे बढ़ने की उम्मीद है। पहले पार्ट में वकील अर्जुन मेहरा के किरदार में नजर आए सनी एक बार फिर मुख्य भूमिका निभाएंगे। अभी इसकी शूटिंग शुरू होने की तारीख और रिलीज को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। 'इक्का' के पहले पार्ट में अक्षय खन्ना ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके और सनी के किरदारों के बीच टकराव कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दोनों कलाकारों को एक साथ देखने का मौका मिलने से भी फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता थी। अब दूसरे पार्ट में अक्षय के शामिल नहीं होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार...' फिल्म की अगली कहानी में उनके किरदार को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरे भाग में सनी देओल के सामने एक नई कहानी और नए किरदार होंगे। फिल्म की कहानी नए सिरे से तैयार की जा रही है।' बता दें कि 'इक्का' सनी देओल के करियर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक रही, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने नेटफ्लिक्स पर अपनी शुरुआत की।





बॉक्स ऑफिस पर 'द वन फोर्स ऑफ द फारेस्ट' को मिली कामयाबी को लेकर खुश हैं तमन्ना

तमन्ना भाटिया इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्हें बॉलिवुड का लकी मस्कट कहा जाता है। वे अपने निर्माता-निर्देशकों के लिए काफी लकी मानी जाती हैं। इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल बिता चुकी तमन्ना साउथ के बाद बॉलिवुड की भी चाहती अभिनेत्री बन गई हैं। इन दिनों वे चर्चा में यहीं अपनी नई फिल्म 'द वन फोर्स ऑफ द फारेस्ट' से। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है और तमन्ना की भूमिका को भी खूब सराहना मिली है।

बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म को मिली कामयाबी को लेकर तमन्ना बहुत खुश हैं। वे कहती हैं, 'इंटरनेट पर मैंने देखा कि लोग थिएटर्स के बाहर चप्पल उतारकर अंदर जा रहे हैं, पॉपकॉर्न की जगह ठेकुआ बांट रहे हैं। बिहार का ये खूबसूरत कल्चर हमने पहली बार इतने बड़े पर्दे पर देखा है। दिवाली और दूसरे त्योहार तो स्क्रीन पर खूब दिखे हैं, लेकिन छठ महापर्व को इस तरह पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही वो पल हैं, जो दर्शकों को जोड़ रह हैं। फोकलोर को सिर्फ रेगुलर तरीके से दिखाने के बजाय उसे बड़े स्टाइल में, खासकर फैमिली ऑडियंस के लिए पेश किया गया है। आज हमें एक ही जॉनर की नहीं, बल्कि मल्टी-जॉनर फिल्मों की जरूरत है, जो अलग-अलग तरह के दर्शकों को एक साथ एंगेज करें और जिनका कोर हमारी संस्कृति से जुड़ा हो। इस फिल्म में छठी मैया के गाने और छठ महापर्व को जिस तरह कहानी का हिस्सा बनाया गया है, उसने दर्शकों को बहुत आकर्षित किया।

इंटरनेट पर मैंने देखा कि लोग थिएटर्स के बाहर चप्पल उतारकर अंदर जा रहे हैं, पॉपकॉर्न की जगह ठेकुआ बांट रहे हैं। बिहार का ये खूबसूरत कल्चर हमने पहली बार इतने बड़े पर्दे पर देखा है। दिवाली और दूसरे त्योहार तो स्क्रीन पर खूब दिखे हैं, लेकिन छठ महापर्व को इस तरह पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही वो पल हैं, जो दर्शकों को जोड़ रह हैं।

ऐसे कांड दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं

हाल ही में तमन्ना एक पौराणिक फिल्म का हिस्सा रही हैं। हमने तमन्ना से जानना चाहा कि एक तरफ हमारे यहां नारियों को पूजा जाता है, मगर दूसरी तरफ आए दिन जमुई कांड और आस्था कुंज गैंगरेप जैसे दरिंदगी से भरी घटनाएं जारी हैं। इस पर वे कहती हैं, 'मेरा मानना है कि समाज में अच्छे भी है और बुराई भी, तो हमारी जिम्मेदारी ये हैं कि हम बार-बार उस अच्छाई को जागरूक करते रहें, क्योंकि बुराई को हम पूरी तरह से रोक तो नहीं पाएंगे। मगर जब हम बार-बार अच्छाई को उभारेंगे, तो उस स्थिति से निपट पाएंगे। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मगर एक कलाकार का काम है कि वह अपनी कला से लोगों को महसूस करा सके कि अच्छाई बाकी है, तो उसे बार-बार बुलंद करना होगा। मेरे हाथ में ये हैं और मैं ये कोशिश लगातार करती रहती हूं।'

माता-पिता हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे

तकरीबन हर लड़की कभी न कभी किसी छेड़खानी का शिकार हुई होती हैं, ऐसे में तमन्ना खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उनके साथ ऐसी घटना कभी हुई। वे कहती हैं, 'मैं बहुत लकी हूं, मेरे माता-पिता ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया। मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। अगर उनका सपोर्ट न होता, तो मुझे जिंदगी के बेस्ट अनुभव नहीं मिलते। मगर मेरा बचपन बहुत शानदार रहा। मेरी किशोरावस्था में भी वे हमेशा मेरे साथ थे। आज भी मेरे पास उनके जैसा एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। मैं इस मामले में भाग्यशाली हूं कि पेरेंट्स के साए ने मुझे हमेशा सुरक्षित रखा। मेरे साथ ऐसा कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ, मगर मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं और मुझे सहानुभूति है। जिनके साथ ऐसा होता है, वो बहुत दर्दनाक होता है।'

पैप्स का जॉब बहुत मुश्किल होता है

पैपराजी की पसंदीदा अभिनेत्रियों में से हैं तमन्ना। उन्हें दूसरे कई कलाकारों की तरह पैप्स से चिढ़ते नहीं देखा है। वे कहती हैं, 'हमारे पैप्स बहुत स्वीट हैं। वो भी हमारे और आपके जैसे लोग हैं। मैं लोगों में अंतर नहीं देखती हूं। वो भी इंसान हैं और बहुत मेहनत करते हैं। कई बार घंटों इंतजार करते हैं कि स्टार्स आएं और वे पिक्स क्लिक करें। उनका काम बहुत मुश्किल है। इंसान बहुत सरल होते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार और सम्मान की चाह होती है। अगर आप उन्हें वो प्रेम और सम्मान दें, तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी।' कंपैनियनशिप के बारे में वे कहती हैं, 'बहुत जरूरी है ये की आपके पास एक अच्छा साथी हो। अच्छा साथी आपको मजबूत और खुशनुमा फील कराता है।'

बारिश में उखड़ी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता, दिन में यातायात प्रभावित न हो इसलिए रात में चल रहा अभियान

त्योहारों से पहले सड़कों को चमकाने में जुटा नगर निगम

■ एक सत बुलेटिन, इंदौर

त्योहारों से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने मरम्मत और डामरीकरण का अभियान तेज कर दिया है। बारिश के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर डामर उखड़ने, गड्ढे बनने और सड़क की सतह क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए निगम ने इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने की कवायद शुरू की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में चार टीमें रात के समय डामरीकरण और मरम्मत का काम कर रही हैं।



अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर के अनुसार, बारिश के कारण जिन सड़कों की स्थिति खराब हुई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराया जा रहा है। निगम का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो और प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारु बना रहे। इसी उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सड़कों को चिह्नित कर चरणबद्ध तरीके से मरम्मत कराई जा रही है। जिन मार्गों पर डामर उखड़ गया है या सड़क की सतह खराब हो गई है, वहां आवश्यकतानुसार डामरीकरण किया जा रहा है। नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत के लिए रात का समय निर्धारित किया है, ताकि दिन में व्यस्त रहने वाले मार्गों पर यातायात को कम से कम प्रभावित किया जा सके। शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और व्यस्त मार्गों पर दिन के समय वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में सड़क पर मरम्मत कार्य होने से जाम की स्थिति बनने और वाहन चालकों को परेशानी होने की आशंका रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए निगम की टीमें रात में डामरीकरण कर रही हैं।

न्यूज ब्रीफ

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शहर में प्रकाश, दुरुस्त सड़कें और साफ-सफाई की रहे समुचित व्यवस्था - कलेक्टर

भिण्ड। कलेक्टर पवन कुमार जैन की अध्यक्षता में महानवमी, दशहरा (विजयादशमी) एवं महर्षि बाल्मिकी जयंती तथा दीपावली के अवसर पर साम्प्रदायिक सौहार्द, सुरक्षा व्यवस्था एवं सतर्कता बरतने के संबंध में शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, सीईओ जिला पंचायत वीरसिंह चौहान, अपर कलेक्टर राजन बी नाडिया, नगर पालिका भिण्ड अध्यक्ष श्रीमती वर्षा बाल्मीकि, जनपद पंचायत भिण्ड अध्यक्ष श्रीमती सरोज बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक के दौरान नगर पालिका भिण्ड को निर्देशित किया कि जुलूस निकलने वाले मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। शहर के मुख्य बाजारों और प्रमुख स्थानों पर जो लाईट बंद पड़ी हैं उनको ठीक कराकर चालू करें, शहर में अभियान चलाकर कचरे का उठाव करें। उन्होंने उपस्थित सभी समिति सदस्यों से शहर की स्वच्छता में अपना सहयोग करने का आव्हान कर कहा कि हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर साफ-स्वच्छ रहे और डोर-टू-डोर कचरे का उठाव कैसे हो सके इसकी भी चिंता हमें करनी होगी। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जगहों पर तार झूल रहे हैं उन्हें व्यवस्थित करें, साथ आने वाले त्यौहारी सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री जैन ने निर्देशित किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की जान से खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारणी जारी

मुरैना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन, मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने तथा उनके निराकरण सहित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संपन्न की जाएगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पुनरीक्षण से संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

लोग दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करने तालाब या नदी के अंदर न जाएं

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शहर में साफ सफाई की रहे समुचित व्यवस्था: कलेक्टर

■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड



कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन की अध्यक्षता में महानवमी, दशहरा (विजयादशमी) एवं महर्षि बाल्मिकी जयंती तथा दीपावली के अवसर पर साम्प्रदायिक सौहार्द, सुरक्षा व्यवस्था एवं सतर्कता बरतने के संबंध में शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री वीरसिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री राजन बी नाडिया, नगर पालिका भिण्ड अध्यक्ष श्रीमती वर्षा बाल्मीकि, जनपद पंचायत भिण्ड अध्यक्ष श्रीमती सरोज बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक के दौरान नगर पालिका भिण्ड को निर्देशित किया कि जुलूस निकलने वाले मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। शहर के मुख्य बाजारों और प्रमुख स्थानों पर जो लाईट बंद पड़ी हैं उनको ठीक कराकर चालू करें, शहर में अभियान चलाकर कचरे का उठाव करें। उन्होंने उपस्थित सभी समिति सदस्यों से शहर की स्वच्छता में अपना सहयोग करने का आव्हान कर कहा कि हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर साफ-स्वच्छ रहे और डोर-टू-डोर कचरे का उठाव कैसे हो सके इसकी भी चिंता हमें करनी होगी। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जगहों पर तार झूल रहे हैं उन्हें व्यवस्थित करें, साथ आने वाले त्यौहारी सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री जैन ने निर्देशित किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की जान से खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ जिन व्यक्तियों के खाद्य पदार्थों में मिलावट का दोष सिद्ध होगा, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोष सिद्ध होने पर आवश्यकता पड़ने पर मकान ध्वस्त करने जैसी कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने उपस्थित समिति सदस्यों से भी सहयोग की अपील कर कहा कि अगर आपके संज्ञान में या आपके आस पास खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले हैं तो उनकी सूचना अपर कलेक्टर को आवश्यक रूप से दें। उन्होंने अपर कलेक्टर और सीएमओ भिण्ड को निर्देशित किया कि महानवमी पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने वाले जितने भी स्थान हैं वहां संपूर्ण व्यवस्था के प्रबंध किए जाएं। जितनी भी छोटी प्रतिमाएं हैं उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर सम्मान के साथ विसर्जित किया जाएगा। बड़ी मूर्तियों का क्रेन, पोकलेन या अन्य संसाधनों की मदद से सम्मान के साथ विसर्जित करने की व्यवस्था की जाए। पूर्व की घटनाओं को देखते हुए लोगों की सुरक्षा हेतु प्रशासन का प्रयास रहेगा कि लोग दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करने तालाब या नदी के अंदर न जाएं।

दिव्यांग आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते



■ एक सत बुलेटिन, इंदौर

हुनर को रोजगार से जोड़कर दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कौशल विकास विभाग ने पहल की है। इंदौर संभाग की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रशिक्षण ले रहे दिव्यांग युवाओं को उनकी योग्यता, तकनीकी दक्षता और कौशल के अनुरूप नौकरी दिलाने में एटिपिकल एडवांटेज सहयोग करेगा। इस उद्देश्य से संयुक्त संचालक कार्यालय, कौशल विकास विभाग, इंदौर संभाग और संस्था के बीच समझौता ज्ञापन किया गया। दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कंपनियों से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। इससे प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप कार्यक्षेत्र चुनने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।संयुक्त संचालक निखिल सिंघल और एटिपिकल एडवांटेज की प्रतिनिधि प्रतीक्षा दुबे ने समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने दिव्यांग युवाओं के नियोजन और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए आपसी समन्वय से काम करने की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर उप संचालक प्रियंका बामने, प्राचार्य रीना सोलंकी, सहायक संचालक पूजा पटेल, प्राचार्य वर्ग-2 गौरव प्रकाश आर्य, संभागीय नियोजन अधिकारी विपिन पुरोहित, संस्था नियोजन अधिकारी हरीश कुमार उईके और प्रशिक्षण अधिकारी विष्णु प्रसाद प्रधान उपस्थित रहे। प्रदेश में विकास गतिविधियों और औद्योगिक विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नए उद्योगों की स्थापना और निवेश को बढ़ावा मिलने से युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर काम के अवसर बढ़ने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

अपर कलेक्टर के नेतृत्व में जांच दल ने राघवेन्द्र डेयरी पर की छापामार कार्यवाही

■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड



कलेक्टर भिण्ड के निर्देशन में अपर कलेक्टर भिण्ड श्री राजन बी नाडिया के नेतृत्व में जांच दल द्वारा आई.टी.आई रोड़ पर स्थित राघवेन्द्र डेयरी पर छापामार कार्यवाही की गई। जांच दल में एसडीएम भिण्ड श्री महेन्द्र सौजन्या, तहसीलदार भिण्ड श्री अरविन्द शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कु. रेखा सोनी एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

कार्यवाही के दौरान राघवेन्द्र डेयरी पर 6000 लीटर दूध, सोर्विटोल, कास्टिक एवं पैक्ड व लूज घी, हाईड्रोजन परऑक्साईड पाये गये। डेयरी पर सोर्विटोल एवं कास्टिक हाईड्रोजन परऑक्साईड जैसे अपद्रव्य मिले। जिनके संबंध में पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित प्रभारी संजीव कुमार द्वारा संतोष जनक जबाव नहीं दिया गया। राघवेन्द्र डेयरी के प्रोपराईटर राघवेन्द्र सिंह तोमर की अनुपस्थिति में मौके पर उपस्थित प्रभारी संजीव कुमार से दूध, घी कास्टिक, सोर्विटोल के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जांच हेतु लिये गये एवं अमृत ब्राण्ड घी 83 लीटर, लूज घी 119 किलो ग्राम, सोर्विटोल 700 किलोग्राम एवं कास्टिक 20 किलोग्राम मौके पर जप्त किया गया। जिसकी कीमत लगभग 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार रूपये) है। डॉक्टर जे.एस. यादव अभिहित अधिकारी एवं लायसेंस प्राधिकारी द्वारा राघवेन्द्र डेयरी का खाद्य लायसेंस निलंबित किया गया।

जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ: 5जी, ब्रॉडबैंड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दम पर भारत के अगले डिजिटल दशक की ओर

■ एक सत बुलेटिन, इंदौर

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड पहले ही भारत की सबसे बड़ी डिजिटल संपर्क सेवा कंपनियों में शामिल है। ब्रोकरेज शोध रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के विकास का अगला चरण और भी बड़ा हो सकता है। 30,213 करोड़ रुपये के जियो प्लेटफॉर्म्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम पहले जीईपीएल कैपिटल, वेंचुरा सिक्योरिटीज और एसएमसी ग्लोबल की रिपोर्टों में 2जी से 4जी और 5जी नेटवर्क पर अपग्रेड, घरेलू ब्रॉडबैंड, उद्यम क्लाउड सेवाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ-साथ विदेशों में जियो की स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल को विकास के प्रमुख माध्यम बताया गया है। ससस 2जी से 4जी और 5जी नेटवर्क पर अपग्रेड में बड़ा अवसर जून 2026 तक जियो का ग्राहक आधार 53.33 करोड़ पहुंच गया था। इसके बावजूद बाजार में बड़ी संख्या में संभावित ग्राहक मौजूद हैं। जीईपीएल कैपिटल के अनुसार, 30 जून 2026 तक करीब 26.10 करोड़ उपयोगकर्ता अभी भी 2जी नेटवर्क पर थे। किफायती पेशकशों और 799 रुपये के जियोभारत फोन जैसे उत्पादों के माध्यम से इन उपयोगकर्ताओं को नए नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की बड़ी संभावना है। कंपनी के ग्राहकों का खर्च भी बढ़ रहा है। औसत प्रति ग्राहक राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में 181.7 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 215.6 रुपये हो गया। वहीं, प्रति ग्राहक मासिक डेटा खपत बढ़कर 43.7 गीगाबाइट पहुंच गई है। मियसमय पर शुल्क में बदलाव, प्रीमियम योजनाओं का बढ़ता इस्तेमाल और इंटरनेट आधारित मनोरंजन, क्लाउड भंडारण, खेल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवाओं को एक साथ उपलब्ध कराने से औसत प्रति ग्राहक राजस्व को और बढ़ाने का लक्ष्य है। जून 2026 तक जियोफाइबर और जियोएयरफाइबर के कुल 2.86 करोड़ ग्राहक थे।

`मेरा करियर, मेरी पहचान' अभियान के तहत हुई गतिविधि

जौरा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सिखाए डिजिटल और एआई कौशल

■ एक सत बुलेटिन, मुरैना।



मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना प्रकोष्ठ के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय जौरा में 'मेरा करियर, मेरी पहचान' अभियान के तहत डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कौशल गतिविधि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराना, उनमें डिजिटल साक्षरता और रचनात्मकता विकसित करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के प्रति जागरूक बनाना रहा। गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, स्वरोजगार और भविष्य में करियर निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रमेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को डिजिटल ज्ञान, तकनीकी दक्षता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। बदलते तकनीकी परिवेश में रोजगार के स्वरूप में हो रहे बदलावों को देखते हुए विद्यार्थियों को समय के साथ अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। डिजिटल साक्षरता के साथ तकनीकी दक्षता पर जोर कार्यक्रम के दौरान डिजिटल साक्षरता और डिजिटल रचनात्मकता के महत्व पर विशेष रूप से चर्चा की गई। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वे तकनीक को समझें और उसका उपयोग अपनी शैक्षणिक तथा व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने में करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव विजयवाड़ा उत्सव में हुए शामिल

हमारी सांस्कृतिक कलाएं और परंपराएं जीवन में भर देती हैं उत्साह और उमंग : मुख्यमंत्री यादव

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सांस्कृतिक कलाएं और परंपराएं जीवन में उत्साह और उमंग भर देती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार देर शाम आंध्र प्रदेश में आयोजित विजयवाड़ा उत्सव में सहभागिता कर रहे थे। कार्यक्रम में 'दक्षिण का वैभव' थीम पर कलाकारों के विभिन्न समूहों ने मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आंध्र प्रदेश सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माँ कनक दुर्गा और भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के चरणों में नमन करते हुए कहा कि विजयवाड़ा उत्सव का यह द्वितीय वर्ष है। नवरात्रि पर्व चल रहा है। मां दुर्गा हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। विजयवाड़ा उत्सव का वैभव ऐसा है कि आज भगवान इंद्र भी इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। बारिश की बूंदें उत्सव के आनंद और उमंग को बढ़ा देती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माँ कृष्णा नदी के किनारे स्थित विजयवाड़ा विजय की धरती है। मध्यप्रदेशवासियों की ओर से हर कार्य में आपकी विजय की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेशवासियों की ओर से आंध्र प्रदेश के नागरिकों को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विविधता से भरी भारतीय संस्कृति में दक्षिण की संस्कृति और परंपराएं हम सभी को रोमांचित करती हैं। देश भर में विजयवाड़ा उत्सव का वैभव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विजयवाड़ा उत्सव के आयोजकों को भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा उत्सव में 4 से 5 हजार कलाकार अपने विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य और कलाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माँ कृष्णा नदी के किनारे स्थित यह पर्वतीय क्षेत्र हीरा खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि यहीं से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला था, जो तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के हाथों में चला गया। भारत सरकार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाने के लिए प्रयास कर रही है। विजयवाड़ा का मैंगो मार्केट देशभर में प्रसिद्ध है।

मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश का संबंध हजारों सालों से रहा है। दोनों राज्य ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध करते हुए परस्पर सहयोग करते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विजयवाड़ा उत्सव में उपस्थित सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं को उज्जैन में बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने सभी को किसी समय लुप्त हुए चीतों को मध्यप्रदेश में तीन स्थानों पर बसाने और प्रदेश की समृद्ध वन्य प्राणी सम्पदा के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विजयवाड़ा उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में टालमटोल का आरोप, राज्य सूचना आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नगर पालिक निगम, भोपाल से जल उपभोक्ता शुल्क एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मांगने के बावजूद आवेदक को मूल अभिलेखों पर आधारित संपूर्ण, स्पष्ट एवं प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस संबंध में अनिकेत द्विवेदी ने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच तथा नियमानुसार जवाबदेही निर्धारित करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार, दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रस्तुत आरटीआई आवेदन में शुल्क वृद्धि, पूर्व एवं संशोधित दरों, शुल्क निर्धारण के कानूनी आधार, गणना प्रक्रिया, बकाया शुल्क पर अधिभार एवं ब्याज, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, संबंधित फाइल नोटिंग, आदेशों तथा अन्य प्रशासनिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। आवेदन के संबंध में नगर निगम के लोक सूचना कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2158/लोकसूका/26, दिनांक 13 अगस्त 2026 के माध्यम से आवेदन को स्वच्छ भारत मिशन, जलकार्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों में मांगे गए अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने के बजाय जानकारी को अन्य शाखाओं से संबंधित बताया गया अथवा कुछ बिंदुओं पर जानकारी निरंक बताई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 325/स्वा.वि./2026 में आवेदन के बिंदु क्रमांक 1 से 7 तक की जानकारी को अपने कार्यालय से संबंधित नहीं बताते हुए निरंक बताया गया। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन एवं जलकार्य विभाग के उत्तरों को लेकर भी शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई है। विभागों से संबंधित बताना पर्याप्त नहीं है; यह स्पष्ट होना चाहिए।

स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय बैरसिया में सेवा संकल्प अभियान का हुआ समापन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में शनिवार 17 अक्टूबर 2026 को सेवा संकल्प अभियान के समापन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ इस अवसर पर अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की गई। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी सिद्धांत जैन ने 17 सितंबर 2026 से संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित समस्त गतिविधियों की समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उनकी प्रगति और उपलब्धियों का विवरण दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.राजू तिलांथे ने अभियान के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए संबंधित प्रभारियों को बधाई दी। साथ ही,कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं ने अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों में अपने अनुभव साझा किए उन्होंने कार्यक्रमों में सहभागिता से प्राप्त अनुभवों और सीख के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में रूपेश जैन ने आभार प्रदर्शन किया इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.शुऐब खान, डॉ.चंद्रकांता अहिरवार सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध गांजे की खेती पर बड़ी कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धार जिले के राजगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम चौबारा के वन क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही गांजे की खेती का पर्दाफाश करते हुए 3,345 गांजे के पौधे, कुल 3,695 किलोग्राम वजन के, जब्त किए हैं।धार जिले के वन क्षेत्र में 3,695 किलोग्राम के 3,345 अवैध गांजे के पौधे जब्त अनुमानित कीमत 4 करोड़ 43 लाख रुपए जब्त पौधों की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 43 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश कैलाश मकवाणा के निर्देशन में संचालित नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा के मार्गदर्शन में थाना राजगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पर राज्य स्तरीय वेबिनार आयोजित किया

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विषय पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश की मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने की। वेबिनार में विषय विशेषज्ञों ने किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों, तनाव, चिंता तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर जानकारी दी। साथ ही, इन समस्याओं की समय पर पहचान, उचित परामर्श एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वेबिनार में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने तथा उन्हें सहयोगपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। संबंधित विभागों, सहयोगी संस्थाओं, शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता से किशोर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान परामर्शदाताओं एवं किशोर-किशोरियों से संवाद भी किया गया। कार्यक्रम में किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान, समय पर परामर्श एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा विद्यालय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील वातावरण विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा वेबिनार का सभी जिलों में यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, साथिया, किशोर-किशोरियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन सहभागिता कर विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की। वेबिनार में लगभग 900 प्रतिभागियों ने सीधे सहभागिता की,जबकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग 11,500 प्रतिभागी जुड़े।

बीना यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के बाद लाइन एवं प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण यात्री ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव

भोपाल। बीना स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के पश्चात लाइन एवं प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण रेल प्रशासन द्वारा यात्री ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ ट्रेनों को निरस्त, कुछ को परिवर्तित मार्ग से संचालित तथा कुछ ट्रेनों को निर्धारित गंतव्य से पहले समाप्त अथवा वैकल्पिक स्टेशन से प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दो ट्रेनों के प्रारंभिक स्टेशन में भी परिवर्तन किया गया है। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है। निरस्त रहने वाली यात्री ट्रेनें 1. बीना-रूठियाई मेमू (61611): दिनांक 17 से 25 अक्टूबर 2026 तक निरस्त रहेगी। कुल 9 फेरे। 2. रूठियाई-बीना मेमू (61612): दिनांक 17 से 25 अक्टूबर 2026 तक निरस्त रहेगी। कुल 9 फेरे। 3. बीना-रूठियाई मेमू (61625): दिनांक 17 से 25 अक्टूबर 2026 तक निरस्त रहेगी। कुल 9 फेरे। 4. रूठियाई-बीना मेमू (61626): दिनांक 17 से 25 अक्टूबर 2026 तक निरस्त रहेगी। कुल 9 फेरे। परिवर्तित मार्ग से संचालित होने वाली ट्रेनें बीना स्टेशन को बायपास करते हुए फ्लाईओवर मार्ग से संचालित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है। 1. बांद्रा टर्मिनस-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19053): दिनांक 16 एवं 23 अक्टूबर 2026 को परिवर्तित मार्ग महादेवखेड़ी-मालखेड़ी-आगासोद होकर संचालित होगी। कुल 2 फेरे। 2. मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस (19054): दिनांक 18 अक्टूबर 2026 को परिवर्तित मार्ग आगासोद-मालखेड़ी-महादेवखेड़ी होकर संचालित होगी। कुल 1 फेरा। 3. गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस (15045): दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को परिवर्तित मार्ग आगासोद-मालखेड़ी।

अनिल कुमार दीक्षित को संख्य योग फाउंडेशन ने सेवा एवार्ड 2026 प्रदान कर सम्मानित किया

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



संख्य योग फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. मुकुल शर्मा एवं अरिहंत हॉस्पिटल, देहरादून के डायरेक्ट डॉ.अभिषेक जैन ने सयुक्त रूप से माया देवी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार दीक्षित की 'स्पिरिट ऑफ़ सेवा एवार्ड 2026 प्रदान कर सम्मानित किया डॉ. अनिल कुमार दीक्षित के 125 शोधपत्र स्कोपस, एल्सवेयर जैसे अंतराष्ट्रीय डाटाबेस जर्नल में प्रकाशित हो चुके है उनके तीन पेटेंट भी ग्रांट हो चुके है ज्ञात हो कि कोरोना काल में रोग से बचाव हेतु सोशल-डिस्टेंसिंग के कामयाब फार्मूला साबित हुआ था इसे डॉ. दीक्षित ने ही 'दो गज़ क़ी दुरी छाते से होगी पूरी' का स्लोगन देकर पूरी दुनियां में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने का एक कारगर हथियार बना दिया था इस सम्मान पर डॉ.अनिल दीक्षित ने अपने छात्रों, शुभचिंतको, सहकर्मीगण, शिक्षकगण एवं परिवार का शुक्रिया अदा किया जिनकी वज़ह से उन्हें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है जो सेवाकार्य के लिये प्रेरित करती रहती है

जीआरपी विदिशा ने मेमो ट्रेन में 10 लाख से भरे बैग की चोरी का किया खुलासा

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मध्यप्रदेश रेल पुलिस द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जीआरपी थाना विदिशा पुलिस ने मेमो ट्रेन में 10 लाख रुपये से भरे बैग की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 लाख 36 हजार रुपए नगद, एक मोबाइल फोन, बैग और मोबाइल चार्जर सहित लगभग 9 लाख 43 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है। 06 अक्टूबर को फरियादी अपने मालिक के निर्देश पर बीना स्थित एक प्लायवुड दुकान से 10 लाख रुपए की राशि लेने गया था। राशि प्राप्त करने के बाद उसने 500-500 रुपये की 20 गड्डियां अपने काले रंग के पिट्ठू बैग में रखीं और बीना से भोपाल जाने वाली मेमो ट्रेन में सवार हो गया। गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण उसने बैग को सीट के ऊपर लगी रेलिंग पर रख दिया। इसके बाद नींद लग जाने से उसे बैग के गायब होने का पता चला। विदिशा रेलवे स्टेशन पर जागने के बाद बैग नहीं मिलने पर उसने जीआरपी थाना विदिशा में शिकायत दर्ज कराई। इस पर अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल अंकित जायसवाल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने फरियादी के आने-जाने के मार्गों एवं संबंधित स्थानों पर लगे लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई।

दुष्यंत संग्रहालय द्वारा वर्ष 2026 के सम्मानों की घोषणा; 28 से 30 दिसंबर तक होगा स्थापना पर्व का तीन दिवसीय आयोजन

शशांक को राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण, संतोष श्रीवास्तव को कमलेश्वर सम्मान

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय, भोपाल द्वारा वर्ष 2026 के साहित्यिक सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। संग्रहालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष श्री रामराव वामनकर ने सम्मानित होने वाले साहित्यकारों के नामों की जानकारी दी। संग्रहालय के स्थापना पर्व के अवसर पर 28 से 30 दिसंबर तक तीन दिवसीय आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 'दुष्यन्त कुमार की साहित्यिक विरासत और इक्कीसवीं सदी का हिन्दी साहित्य' विषय पर शोध संगोष्ठी के साथ अन्य साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अलंकरण एवं सम्मान समारोह आयोजित होंगे। वर्ष 2026 के लिए घोषित सम्मानों में राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण श्री शशांक को प्रदान किया जाएगा। वहीं, सुदीर्घ साहित्य साधना सम्मान श्री खीमन मूलाणी, आंचलिक भाषा सम्मान श्री नरेंद्र बहादुर तथा दुष्यंत युवा रचनाकार सम्मान श्री अरुणाभ सौरभ को दिया जाएगा। संग्रहालय द्वारा घोषित स्मृति सम्मानों में कमलेश्वर सम्मान श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, बालकवि बैरागी सम्मान श्री धर्मेंद्र सोलंकी, विट्ठल भाई पटेल सम्मान श्रीमती मधु शुक्ला, कन्हैयालाल नंदन सम्मान डॉ. रंजना शर्मा तथा शरद जोशी सम्मान डॉ. साधना बलवटे को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण के साथ 21 हजार रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। सुदीर्घ साहित्य साधना सम्मान एवं आंचलिक भाषा सम्मान के अंतर्गत 11-11 हजार रुपये तथा दुष्यंत युवा रचनाकार सम्मान के अंतर्गत 7 हजार रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी। स्मृति सम्मानों से सम्मानित होने वाले प्रत्येक रचनाकार को 5 हजार रुपये की सम्मान निधि के साथ शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। 28 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले स्थापना पर्व में 'दुष्यन्त कुमार की साहित्यिक विरासत और इक्कीसवीं सदी का हिन्दी साहित्य' विषय पर शोध संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में दुष्यन्त कुमार के साहित्यिक अवदान, उनकी रचनात्मक दृष्टि की प्रासंगिकता तथा इक्कीसवीं सदी के हिन्दी साहित्य में उनकी विरासत के प्रभाव और विस्तार पर विचार-विमर्श होगा। इसके साथ साहित्य, भाषा और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़े अन्य विषयों पर भी संवाद एवं साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थापना पर्व के दौरान अलंकरण एवं सम्मान समारोह भी होंगे। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय साहित्यिक धरोहरों के संरक्षण, साहित्यिक-सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न पीढ़ियों के रचनाकारों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से निरंतर सक्रिय है। संग्रहालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले ये सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को पहचान देने और साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल हैं। पत्रकार वार्ता में संग्रहालय की निदेशक करुणा राजुरकर, उपाध्यक्ष मनोज मीक, घनश्याम मैथिल 'अमृत', कोषाध्यक्ष रमेश भुमरकर सहित कार्यकारिणी के सदस्य वी. के. श्रीवास्तव, बिहारी लाल सोनी 'अनुज', इंदिरा दांगी, मौसमी परिहार, श्रद्धा यादव, प्रिंस और दृष्टिपाल सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति भोपाल के लिए, प्रकाशक एवं मुद्रक, **संपादक अमित शर्मा** द्वारा ए -1 माचना कॉलोनी , शा. राजीव गांधी स्कूल के पास, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) पिन - 462016 से प्रकाशित एवं विनर प्रिंटर्स प्लाट 241-242 डायनामिक सेन्टर, एमपी नगर जोन-1 भोपाल से मुद्रित। **स्थानीय संपादक सुनील नायक**, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI- MPHIN/2018/76807/ E-mail-eksatbulletin@gmail.com, डाक पंजीयन नंबर MP/BHOPAL/4-501/2020-22, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें- फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088